● वर्ष-2
● अंक-291
रायपुर, शुक्रवार
28 जुलाई 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

संसद में विपक्ष का बवाल लगातार जारी

विपक्षी दलों के नेता संसद भवन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र का आज छठा दिन है। हालांकि, बवाल लगातार जारी है। दरअसल, मणिपुर को लेकर विपक्षी दल लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्षी दलों की मांग यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर को लेकर बयान देना चाहिए। विपक्षी दलों के नेता आज संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। इसको लेकर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है? जिनका मन और तन काला है, उनके दिल में क्या छुपा है?

मातम में पहनते हैं काले कपड़े-अनिल विज

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने तो यह तक कह दिया कि मातम में ही काले कपड़े पहने जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि नई पार्टी का कोई स्वर्ग सिधार गया होगा। अनिल विज का नई पार्टी से संदर्भ इंडिया गठबंधन से था जो विपक्षी दलों की एकता का मंच है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि काले कपड़े तो मातम में ही पहने जाते हैं। यह जो नई पार्टी बनी है उसके जन्म के साथ ही कोई स्वर्ग सिधार गया होगा इसलिए ये काले कपड़े पहनकर आए हैं। विज ने कहा कि सरकार के लिए सभी धर्मों के लोग एक समान है, इसके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है।

दूसरी ओर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं लेकिन मणिपुर पर

संसद में बयान नहीं दे रहे। संसद के दोनों सदनों में आज कुछ कामकाज भी हुए हैं।

लोकसभा की कार्यवाही

मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण बृहस्पतिवार को सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

लोकसभा ने बृहस्पतिवार को 'निरसन एवं संशोधन विधेयक 2022' को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके माध्यम से वर्षों पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान किया गया है जिनमें एक कानून 138 वर्ष पुराना है। सदन में विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक 'कारोबार सुगमता' और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के सरकार के सिद्धांत के अनुरूप है।

देश में वर्ष 2004 से 2014 के दौरान परिणामी रेल दुर्घटनाओं की औसत संख्या प्रति वर्ष 171 थी जो वर्ष 2014 से 2023 के दौरान औसतन 71 प्रतिवर्ष दर्ज की गई। सरकार ने लोकसभा को यह जानकारी दी। लोकसभा में अरविंद सावंत के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यह जानकारी दी।

राज्यसभा की कार्यवाही

मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान की मांग को लेकर विपक्षी दलों के भारी हंगामा और शोरगुल आज भी राज्यसभा में जारी रहा।

राज्यसभा में बृहस्पतिवार को काले कपड़े पहन कर आये विपक्षी दलों के सदस्यों पर तीखा प्रहार करते हुए सदन के नेता पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा विदेश नीति जैसे गंभीर विषय पर राजनीति करना 'दुर्भाग्यपूर्ण' है तथा उनका विगत और वर्तमान ही नहीं भविष्य भी 'काला' है।

सरकार ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कहा कि पायरेसी एक ''दीमक'' की तरह भारतीय फिल्म उद्योग को खा रही है और इसको रोकने के लिए लाये गये चलचित्र (संशोधन) विधेयक से उद्योग के हर सदस्य को लाभ मिलेगा और सिनेमा के माध्यम से भारत एक ''साफ्ट पॉवर'' की तरह तेजी से उभरेगा। फिल?म उद्योग में पायरेसी मुद्दों को नियंत्रित करने पर केन्द्रित चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023 चर्चा के बाद राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया।

मणिपुर को लेकर भाजपा में भी उठने लगे विरोध के सुर, विनोद शर्मा का पार्टी से इस्तीफा

नई दिल्ली। मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शर्मा ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के बयान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की स्थिति ने भारत को बदनाम किया है। उन्होंने कहा कि मैंने भारी मन से भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर की स्थिति ने भारत को बदनाम किया है। मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न घुमाने का भयावह वीडियो सामने आने के बाद से बीजेपी की राज्य सरकार और केंद्र निशाने पर है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष जातीय संघर्षग्रस्त मणिपुर की स्थिति पर संसद में प्रधान मंत्री से बयान देने और उसके बाद इस पर पूर्ण चर्चा की मांग कर रहा है। अपने बयान में विनोद शर्मा ने कहा कि भारी मन से मैंने जेपी नड्डा और पीएम मोदी को लिखा कि मणिपुर के वीडियो जैसी घटना कहीं और नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि फिर भी पीएम सो रहे हैं, उनमें सीएम बीरेन सिंह को बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं है। इंसानियत के नाते मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मामला उठाया। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के एक दिन बाद, विभिन्न विपक्षी दलों के नेता, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं।

इन दिनों

✍ जितेंद्र

राजस्थान सियासत में लाल डायरी की कहानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा ने राजस्थान में सियासी हलचल तेज कर दी है। पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार और विपक्ष के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने एक लाल डायरी का जिक्र किया। कहा जा रहा है कि इस बार का राजस्थान विधानसभा चुनाव इस लाल डायरी के इर्द-गिर्द ही घूमने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, %कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है और झूठ का बाजार चलाया है। झूठ की दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, राजस्थान की %लाल डायरी%। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कह रहे हैं कि %लाल डायरी% के पन्ने खुले तो अच्छे-अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा लें, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। पिछले शुक्रवार को राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया। राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पर चर्चा हो रही थी। इस बीच, कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए मणिपुर हिंसा की तख्तियां लहराने लगे। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी सदन में मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, सच्चाई ये है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गुढ़ा के तीखे हमलों से राजस्थान कांग्रेस की सरकार असहज हो गई। आनन-फानन में अशोक गहलोत ने गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद गुढ़ा रोते हुए मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि मुझे सच बोलने की सजा मिली है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर वन है। मैंने क्या गलत कहा? जनता मेरे साथ रहेगी और मैं उनके लिए काम करता रहूंगा। चाहे वह मुझे कैबिनेट से हटाएं या जेल भेज दें। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, बोलता रहूंगा। मैं अशोक गहलोत से इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहता था। राज्य में पुलिस भ्रष्ट है। वे लोगों से रिश्वत लेने में व्यस्त हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने मीडिया से इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने दावा किया कि इस डायरी में कांग्रेस के नेताओं के काले कारनामे की पूरी जानकारी है। किस तरह से कौन सा नेता अपने ऊपर फिल्में बनवा रहा है? राज्यसभा में कांग्रेस ने विधायकों को क्या-क्या और कैसे दिया? क्रिकेट के चुनाव में अशोक गहलोत ने किस-किसको पैसे दिए? कहां-कहां से वसूली होती है? गुढ़ा के मुताबिक, डायरी का एक हिस्सा कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने सदन के अंदर छीन लिया। हालांकि, दूसरा हिस्सा अभी भी गुढ़ा के पास है।

30 फीसदी में गंभीर हो सकती है आई फ्लू की समस्या

तेजी से बढ़े आई फ्लू के मरीज

नई दिल्ली। मौसमी बीमारी के साथ ही राजधानी के सभी अस्पतालों में डेढ़ से दोगुना तक मरीज बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में अभी इससे राहत की उम्मीद नहीं है। ऐसे में बढ़ती बीमारी को देखते हुए एम्स ने भी गुरुवार को ट्वीट कर आई फ्लू से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि गर्मी के मौसम के अंत और मानसून की शुरुआत में यह बीमारी फैलती है। इस मौसम में मक्खियों की अधिकता के कारण यह संक्रमण होता है। ऐसे में बचाव के लिए वातावरण साफ रखना चाहिए।

डॉक्टरों का कहना है कि आई फ्लू की समस्या एक से दो सप्ताह में अपने आप

ठीक हो जाती है। इसे लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि बचाव को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है। एम्स में नेत्र विज्ञान विभाग की प्रोफेसर डॉ. नम्रता शर्मा ने बताया कि संक्रमण से बचकर ही आई फ्लू को कम किया जा सकता है। इसमें मरीज की आंख के सफेद हिस्से में संक्रमण होता है, जो जल्द ठीक हो सकता है, लेकिन 30 फीसदी मरीजों में यह पुतली को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में गंभीर मरीजों की आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। यह बीमारी देखने से नहीं, बल्कि संक्रमित जगह को छूने या मरीज के संपर्क में आने से होती है। ऐसे में बचाव को लेकर विशेष ध्यान रखना चाहिए।

एक माह तक जिंदा रहता है वायरस

आई फ्लू का वायरस एक माह तक जिंदा रह सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि आई फ्लू देखने से नहीं फैलता, बल्कि संक्रमित जगह को छूने से फैलता है। संक्रमित मरीज जिस जगह को छूता है वहां वायरस एक माह तक जिंदा रह सकता है। ऐसे में इससे बचाव के लिए संक्रमित मरीज को आइसोलेट करना चाहिए। साथ ही, इस्तेमाल के कपड़ों को अलग रखना चाहिए। सफाई का विशेष ध्यान रखने से इसका प्रभाव तेजी से घटता है।

यह है लक्षण

- आंखें लाल होना
- आंखें चिपचिपी होना
- आंखों में सूजन होना
- खुजली व पीले रंग का पानी आना
- आंखों में चमक लगना

अस्पताल में दोगुना हो गए मरीज

अस्पताल के निदेशक डॉ. सुरेश कुमार ने कहा कि आई फ्लू की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंच रहे मरीजों की संख्या डबल हो गई है। अब अस्पताल में रोजाना 40-50 मरीज आ रहे हैं। 100 से अधिक निजी अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीज आई फ्लू की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।

प्रमुख समाचार

मणिपुर वायरल वीडियो की जांच करेगी सीबीआइ

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से ठीक 1 दिन पहले मणिपुर से संबंधित एक वीडियो जबर्दस्त तरीके से वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में दो नग्न महिलाएं साफ तौर पर देखी जा रही थी। इसके बाद पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

खुद क्रोध व्यक्त किया था और कहा था कि यह देश को शर्मसार करने वाला वीडियो है। इन सबके बीच गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। गृह मंत्रालय मणिपुर वायरल वीडियो मामले को सीबीआई को भेजेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर वायरल वीडियो मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने का अनुरोध करेगा। सूत्रों का दावा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर मामले को लेकर अपनी पहली नजर रख रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार मणिपुर पर अधिकारियों से हर अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि मणिपुर में 35000 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। सेना, सीआरपीएफ, सीआरपीएफ के 35000 जवानों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा मैतेई और कुकी समुदायों के बीच बफर जोन बनाया गया है।

तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारतः एसबीआई

नई दिल्ली। एसबीआई रिसर्च ने अपनी इकोरैप रिपोर्ट में कहा है कि यदि भारत अपनी वृद्धि की मौजूदा दर को बरकरार रखता है तो यह जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़कर 2027 (2027-2028) में दुनिया तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। इससे पहले एसबीआई रिसर्च ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। रिपोर्ट के अनुसार दिलचस्प बात यह है कि 2022-2027 के बीच भारत की वृद्धि ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकार 1.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है, इस दर से भारत हर दो साल में अपनी इकोनॉमी में 0.75 अरब डॉलर जोड़ सकता है, जिसका मतलब है कि भारत 2047 तक 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। 2027 तक वैश्विक जीडीपी में भारत का योगदान चार प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में भारत की जीडीपी का हिस्सा फिलहाल 3.5 प्रतिशत है, जो 2014 में 2.6 प्रतिशत था और इसके 2027 में चार प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

कोयला घोटाले में पूर्व सांसद को मिली 4 साल की सजा

नई दिल्ली। दिल्ली की विशेष अदालत ने यूपीए काल के कुख्यात कोयला घोटाले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा को चार साल जेल की सजा सुनाई है। विजय दर्डा के साथ-साथ

उनके बेटे देवेन्द्र दर्डा को भी छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता के आरोप में चार साल जेल की सजा सुनाई गई है। जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयासवाल को भी पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता के साथ चार साल जेल की सजा सुनाई गई, जबकि केएस क्रोफा और केसी सामरिया को 3 साल जेल की सजा मिली। दिल्ली कोर्ट ने मेसर्स जेएलडी यवतमाल पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोयला आवंटन घोटाले को देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक करार दिया गया था, जिससे सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ था, जिसने 2012 में मनमोहन सिंह सरकार को भी हिलाकर रख दिया था। कार्यवाही के दौरान, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कहा कि कोयला आवंटन घोटाले में 13वीं सजा सुनिश्चित की गई थी।

ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले में 3 अगस्त को फैसला

इलाहाबाद। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीसरे दिन सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद इलाहबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मुख्य

न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश 3 अगस्त तक जारी रहेगा। यानी एएसआई सर्वे पर स्टे 3 अगस्त तक जारी रहेगा। आज सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि अब, मुख्य निर्णय कौन सा है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं। जवाब में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुख्य मामले जिनका मैंने कल हवाला दिया था। मुद्दा यह है कि अंजुमन इंतेज़ामिया के वरिष्ठों द्वारा जो भी निर्णय उद्धृत किए गए थे, उन पर इस अदालत ने अविश्वास किया है? सीजे ने अब जैन से अपनी दलीलें संक्षेप में बताने को कहा। जैन ने वरिष्ठ वकील नकवी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने श्रीकांत मूलचंद मामले का हवाला दिया था, लेकिन इस अदालत ने कहा है कि फैसला गलत था। यह हर मामले में पालन किया जाने वाला नियम नहीं है।

15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे ईडी निदेशक एसके मिश्रा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की

मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक के तौर पर एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या पूरा विभाग अक्षम लोगों से भरा है जो केंद्र ईडी निदेशक के कार्यकाल में विस्तार चाहता है। न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम यह क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं कि ईडी निदेशक पद के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, क्या पूरा विभाग अक्षम लोगों से भरा है? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह स्पष्ट कर दिया कि आगे कोई कार्यकाल विस्तार नहीं होगा। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि वह राष्ट्रीय हित में कार्यकाल विस्तार पर फैसला दे रहे हैं। वहीं शीर्ष कानून अधिकारी ने पीठ के समक्ष तर्क दिया कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की सहकर्मी समीक्षा के मद्देनजर ईडी नेतृत्व की निरंतरता आवश्यक है।

कर्नाटक में पांच गारंटी बनी नई सरकार के गले की फांस!

चुनावी मौसम में नेताओं और राजनीतिक दलों की ओर से जनता को लुभाने के लिए कई तरह के लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। लोकतंत्र में यह परंपरा शुरू से रही है। इससे जनता को भी अपनी पसंद के उम्मीदवार और पार्टी चुनने में मदद मिलती है। साथ ही साथ पार्टियों को भी जनता तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। समय-समय पर चुनावी वादों को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से पांच गारंटी जनता के समक्ष रखे गए थे। कांग्रेस का दावा था कि गारंटियों को हम हर हाल में पहले ही कैबिनेट की बैठक में लागू करेंगे। इसके बाद कांग्रेस को कर्नाटक में जबरदस्त सफलता मिली। अब कांग्रेस अलग-अलग राज्यों में भी गारंटी की बात कर रही है।

डीके शिवकुमार का बयान

इन सबके बीच कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से कांग्रेस की गारंटी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, डीके शिवाकुमार ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस सरकार इस साल ज्यादा विकास नहीं कर सकती। बताया जा रहा है कि शिवकुमार ने अपने विधायकों को विधायक दल की बैठक में इस बात से अवगत कराया। डीके शिवकुमार का मकसद नाराज नेताओं को 5 गारंटियों को लागू करने में आ रही वित्तीय बाधाओं को समझाना था। पिछले दिनों विधायकों की ओर से विकास कार्यों में देरी और मंत्रियों की पहुंच से बाहर होने पर नाराजगी व्यक्त की गई थी। डीके शिवकुमार कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने साथ ही विधायकों से यह भी

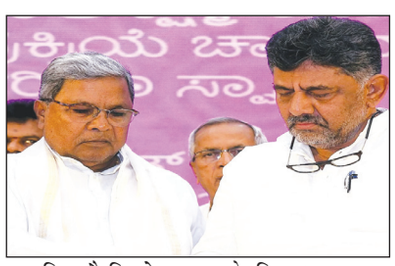

कह दिया है कि वे 1 साल के लिए अनुदान ना मांगे।

विधायकों में नाराजगी

डीके शिवकुमार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले दिनों 11 विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को एक पत्र लिखा गया था। इस पत्र के जरिए मंत्रियों की कार्यशैली और विकास कार्यों को लेकर चिंता जताई गई थी। विधायकों ने दावा किया था कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास को लेकर जनता से जो वादे किए गए थे उस पर अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिल रही। दूसरी ओर डीके शिवकुमार ने कहा कि हमें इस साल 5 गारंटियों के लिए 40000 करोड रुपए अलग से रखने पड़े हैं। यही कारण है कि हम विकास के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। डीके शिवकुमार के पास जल संसाधन और बेंगलुरु शहर विकास मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। हालांकि, उन्होंने कहा कि हम सिंचाई और सार्वजनिक कार्यों में भी विकास के लिए राशि जारी नहीं कर सकते।

क्या है पांच गारंटी

कर्नाटक में चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जो 5 गारंटी दिए थे उनमें गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया को गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2000 रुपये की मासिक सहायता, बीपीएल परिवार को अन्न भाग्य योजना के तहत प्रतेक सदस्य को 10 किलोग्राम मुक्त चावल, बेरोजगार स्नातक युवाओं के लिए हर महीने 3000 रुपये और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए 1500 रुपए और सार्वजनिक परिवहन बसों में शक्ति योजना के तहत महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा शामिल है। जाहिर सी बात है कि योजना ऐसी है जहां सरकारी खजाने से भारी पैसा खर्च होता है। कांग्रेस की ओर से इसे लागू करने की शुरुआत भी हो चुकी है। यही कारण है कि कई दूसरी परियोजनाओं में कांग्रेस को कटौती करनी पड़ रही है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इसको लेकर भाजपा पर निशाना साध रही है। सिद्धारमैया हो या फिर डीके शिवकुमार, वर्तमान परिस्थिति के लिए नेताओं की ओर से पिछली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि पिछली सरकार ने दिवालियापन पैदा कर दिया था। जरूरत से ज्यादा टेंडर जारी कर खजाने को खाली कर दिया था। हमें अपने गारंटी को लागू करने के लिए अपना वादा निभाना था। हमने अपने पहले ही साल में वादा निभाया है। इसलिए सभी को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है।

पूरे प्रकरण को साधारण शब्दों में समझने की कोशिश करें तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि नेताओं और राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव के दौरान जो वादे किए जाते हैं, उसको लेकर कोई ठोस नीति या रणनीति पर चर्चा नहीं की जाती।

मुख्यमंत्री का बोरिया बिस्तर तैयार, बन रही भाजपा की मजबूत सरकार : साव

■ गांव, गली में गोबर घोटाले की गूंज, लोग कह रहे- बदलबो - बदलबो ये दारी छत्तीसगढ़ म कांग्रेस के सरकार ल बदलबो

धमतरी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मंगलवार को दो दिवसीय जिले के प्रवास पर थे। साव का यह दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। सिहावा व धमतरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने चौक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी का भव्य स्वागत किया। बैठक के पूर्व अरुण साव ने प्राचीन कर्णेश्वर मंदिर का दर्शन किया और प्रदेश की खुशहाली का कामना की तत्पश्चात साव ने सिहावा और धमतरी में विधानसभा कोर टीम के साथ आगामी चुनाव को लेकर बैठक की। इसमें केंद्रीय नेतृत्व से प्राप्त दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई।

साव ने बैठक में कार्यकर्ताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जोश भरा। उन्हें जीत के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट जाने के लिए प्रेरित किया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी प्रदेश में मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। भाजपा की तैयारी से कांग्रेस में भय व्याप्त है। इसलिए प्रदेश में उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री तक को बदलना पड़ा। ये आप जैसे मेहनती कार्यकर्ताओं के मेहनत का परिणाम है। इस बार जनता ने इस सरकार को बदलने का मन बना लिया है। इस बार बीजेपी की जीत निश्चित है। आप लोग इसी तरह मैदान में डटे रहना है।

साव ने प्रदेश स्तरीय, संभाग स्तरीय, विधानसभा स्तरीय व मंडल स्तर पर संगठन के कार्यक्रमों को लेकर बातचीत की। वहीं विधानसभा कोर टीम के अलावा पूर्व पदाधिकारियों के साथ भी अलग से बैठक की।

बैठक को लेकर साव ने मीडिया को बताया कि हम सबका लक्ष्य केवल एक है। राज्य की अत्याचारी कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। प्रदेश को और यहां के जनता को पुनः विकास के मार्ग पर आगे ले जाना है। कांग्रेस सरकार ने अपने भ्रष्ट आचरण का परिचय इन पौने 5 साल में दिया है।

कांग्रेस शासन में एक भी दिन ऐसा नहीं, जब आपराधिक घटनाओं से राजधानी रायपुर दहला न हो। 15 वर्षों में जिस प्रदेश को भाजपा ने गढ़ने, संवारने का काम किया। उसे भूपेश बघेल की सरकार ने अपराध का गढ़ बना दिया है।

प्रदेशवासी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। गौठान में किस तरह से घोटाला हुआ। गोबर के नाम पर छत्तीसगढ़ का धन किस तरह से लूटा गया। छत्तीसगढ़ का किसान किस तरह से परेशान है। उन्हें न बीज मिला रहा है, न ही खाद मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार न ही अब फसल बीमा का लाभ देने का प्रयास कर रही है।

भ्रष्टाचारी भूपेश सरकार के इरादों को छत्तीसगढ़ की जनता ने भलीभांति पहचान लिया है। अब इनके झूठे वादों और इरादों में जनता फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ से बोरिया बिस्तर बांध लें, क्योंकि यहां से जाने का समय आ गया है।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शशि पवार, विधायक धमतरी रंजना साहू,नीलू शर्मा,रामू रोहरा, हलधर साहू,राजीव पांडे,इंदर चोपड़ा,प्रीतेश गांधी,कविंद्र जैन, अरविंदर मुंडी, अर्चना चौबे, चेतन हिंदुजा, बीथिका विश्वास, श्यामा नरेश साहू, हेमंत माला, विजय साहू, उमेश साहू, हेमंत चंद्राकर, मुरारी यदु, कैलाश सोनकर, चंद्रकला पटेल, दमयंतीन साहू, खुबलाल ध्रुव, विनोद पांडे सहित भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

वरिष्ठ भाजपा नेता गजराज जैन एवं जिला महामंत्री कविंद्र के निवास पहुँचे प्रदेश अध्यक्ष

मंगलवार सुबह श्री साव ने सिहावा विधानसभा के कोर ग्रुप एवं पूर्व पदाधिकारियों की बैठक ली उसके पश्चात देर शाम तक जिला भाजपा कार्यालय मे कोर ग्रुप तथा पूर्व पदाधिकारियों की मैराथन बैठक ली। इस दौरान उन्होंने चुनाव की दृष्टि से 15 से अधिक विशेष कार्य हेतु प्रमुख नेताओं के मध्य कार्यविभाजन किया। बैठक के उपरांत श्री साव एवं वरिष्ठ नेताओं ने रात्रि भोजन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष स्व श्रीमती जानकी पवार के निवास पर किया तथा उनके परिवारजनों तथा समाज जनों से मुलाकात की । श्री साव सहित नेता गण शहर के सुप्रसिद्ध गोकुल पान ठेले पर खड़े होकर पान का आनंद लेते हुए स्थानीय लोगों से भी बातचीत की ।

रात्रि विश्राम पीडब्लूडी विश्राम गृह मे करने के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष ने सुबह वयोवृद्ध भाजपा नेता गजराज जैन तथा जिला महामंत्री कविंद्र जैन के निवास पहुँच कर परिवार जनों से सौजन्य भेंट की । श्री साव के साथ जिला संगठन प्रभारी नीलू शर्मा, जिलाध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, संगठन सह प्रभारी हलधर साहू, रामु रोहरा, अरविंदर मुंडी, डेनिस चंद्राकर, खुबलाल ध्रुव, सूरज शर्मा सहित प्रमुख नेतागण भी श्री जैन के निवास पहुँचे ।

एक-एक कार्यकर्ता की चिंता करनी है: अरुण साव

नगरी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव गत दिनों सिहावा में विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारी कोर समिति की बैठक लिए। बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि राजनीति कोई व्यापार नहीं है, राजनीति को मस्ती से हंसते हुए संगठन के लिए काम करें। जितने अच्छे मूड से काम करोगे उतनी एक-एक कार्यकर्ता और जनता के बीच जा पाओगे। पार्टी ने पद दिया है तो उसका सम्मान करें। पार्टी को बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वयं की होनी चाहिए। चुनाव जीतने के लिए जोश और हर्ष- उल्लास के साथ बूथ में जाना होगा तभी हम बूथ जीत सकते हैं। और बूथ जीतेंगे तो विधानसभा और विधानसभा जीतेंगे तो राज्य। एक-एक कार्यकर्ता की चिंता पदाधिकारी को करनी है। मंडल की बैठक में जितने लोग आते हैं स्वागत योग्य है किंतु जो नहीं आते उनकी चिंता पदाधिकारियों को करनी है। टीम भावना के साथ काम करना है। संगठन के पदाधिकारी होने के नाते जनता की समस्याओं को लेकर शासन प्रशासन तक जाना है। बैठक में बस्तर महाराजा कमल चंद्र भंजदेव, लोकसभा प्रभारी यशवंत जैन, जिला सह प्रभारी हलधर साहू, अजजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम, जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, पूर्व विधायक श्रवण मरकाम, जिला महामंत्री प्रकाश बैस, जिला मंत्री राजेन्द्र गोलछा, जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी, रविशंकर दुबे के साथ चारों मंडल के प्रभारी, अध्यक्ष, महामंत्री, उपस्थित थे।

अरूण साव ने कर्णेश्वर महादेव की पूजा अर्चना की : सिहावा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने देउरपारा (सिहावा) स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। कर्णेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विकल गुप्ता ने श्री साव का ट्रस्ट की ओर से स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सिहावा श्रवण मरकाम, भाजपा जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार,जिला सह प्रभारी हलधर साहू, जिला मंत्री प्रेमलता नागवंशी,वरिष्ठ भाजपा नेता नागेन्द्र शुक्ला, कमल डागा, सांसद प्रतिनिधि मोहन पुजारी, मीडिया प्रभारी रामगोपाल साहू आदि उपस्थित थे।

विधायक रंजना झूठा श्रेय लेने का कर रहा प्रयास : कांग्रेस पार्षद दल

■ शहर में विकास कार्यों के लिए 638 लाख रुपये की मिली स्वीकृति

धमतरी। शासन के द्वारा धमतरी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में 638 लाख रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिस पर राजनीति शुरू हो गई है विधायक रंजना साहू के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए नागरिकों की मांग पर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 65 लाख रुपये की विकास कार्य स्वीकृत कराने की बात कही गई थी। जिस पर कांग्रेस पार्षद दल के द्वारा विधायक पर झूठा श्रेय लेने का प्रयास बताया है।

कांग्रेस पार्षद दल के प्रवक्ता सोमेश मेश्राम ने विधायक को निष्क्रिय बताते हुए कहा कि विधायक क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास कार्यों पर झूठी श्रेय लेने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के गौरव समागम-2023 में 10 करोड़ की राशि धमतरी नगर निगम के विकास कार्य हेतु घोषणा की गई थी। जिस पर विभागीय मंत्री शिव डहरिया के द्वारा महापौर विजय देवांगन के अनुशंसा के आधार 638 लाख रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिनमे से कुछ विकास कार्य अपना बता कर विधायक झूठी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों पर झूठा श्रेय लेने विधायक महोदया का पुराना नाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में नकारने के बाद कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में शहर याद आ रही है यदि वे स्वयं एक भी बार अपने खुद

के दल के पार्षदों के साथ बैठाकर नगर विकास की कोई योजना बनाएं है तो बता दे शहर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। पार्षद नीलू पवार ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास कार्य तेज गति से हो रही है। पिछले 15 वर्षों के भाजपा शासनकाल के दौरान शहर के नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे थे आज नगर निगम में महापौर विजय देवांगन, सभापति अनुराग मसीह सहित पूरी निगम की टीम शहरी क्षेत्र में विकास के साथ-साथ लोगों की बेहतरी के लिए कार्य कर रहे। विधायक महोदया का विकास कार्यों में झूठी श्रेय लेने का पुराना नाता रहा है। जो प्रयास आज भी जारी है क्षेत्र की जनता जागरूक है और वह भली-भांति जानती है लोगों की हित की लड़ाई कौन लड़ रही है। ब्लॉक कांग्रेस शहर 01 के अध्यक्ष आकाश गोलछा ने कहा कि महापौर जी द्वारा लगातार निगम क्षेत्र में विकास कार्य करवाया जा रहा है। 638 लाख के विकास कार्यों से निश्चित ही शहरवासियों के मूलभूत आवश्यकता है पूर्ण होगी। भाजपा के लोग अपने विधायक की नाकामी छुपाने महापौर के ऊपर आरोप लगाते। और विधायक के द्वारा महापौर द्वारा कराए गए विकास कार्यों पर झूठी श्रेय लिया जाता है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर 02 के अध्यक्ष ईश्वर देवांगन ने कहा कि विधायक महोदया ग्रामीण क्षेत्रों में शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों को लेकर श्रेय लेने की राजनीति करती आ रही है जो सर्वविदित है कोलियरी-खरेंगा-झुरातराई मार्ग में झूठी श्रेय लेने पर पदयात्रा के दौरान उनके ही पार्टी के नेताओं के द्वारा काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया। निष्क्रिय विधायक के नाम से पहचाने जाने वाले विधायक महोदया अब शहरी क्षेत्र के कार्यों में झूठी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। निगम क्षेत्र में इन कार्यों की मिली है स्वीकृति। हटकेशर वार्ड क्रमांक 01 में समुदायिक भवन निर्माण कार्य 25.00, नया बस स्टैण्ड परिसर में आधुनिक शौचालय निर्माण कार्य 26.24, सदर दक्षिण वार्ड क्रं. 24 में कैलाश सोनकर घर से मुकेश सोनकर बाड़ी तक सीसी रोड निर्माण कार्य 5.77, सदर दक्षिण वार्ड क्रं. 24 में उमेश डेयरी से अरूण पान ठेला तक सीसी रोड निर्माण कार्य 2.20, औद्योगिक वार्ड क्र। 07 में ओरकल पब्लिक स्कूल से राज किराना से एनएच 30 तक सीसी रोड निर्माण कार्य 16.91, बनियापारा वार्ड क्रं। 28 में वैष्णवी मंदिर से अख्तर भाई दुकान तक सीसी रोड निर्माण कार्य 11.60,नयापारा वार्ड क्रं 32 में सरजू गली घर से विष्णु होटल तक सीसी रोड निर्माण कार्य 10.60, विध्यवासिनी वार्ड क्र 18 में महेश पटवा घर से अखिलेश सोनकर घर से शैलेन्द्र पटेल घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य 1.83,विंध्यवासिनी वार्ड क्रं 18 में कमलनारायण घर से कुन्ती बंजारे घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य 1.93,सोरिद वार्ड क्र 35 में विक्टोरिया घर से लेकर अनमोल दौलत घर तक (डिपोपारा) सीसी रोड निर्माण कार्य 5.17,सोरिद वार्ड क्रं 35 में बागतराई रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउण्ड सोरिद वार्ड में सीसी रोड निर्माण कार्य 24.17, सोरिद वार्ड क्र 35 में स्क्रीनिंग मशीन हेतु शेड निर्माण कार्य 7.05, सोरिद वार्ड क्र 35 में एनएच 30 से लेकर मसीह सर घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य 4.25, नवागांव वार्ड क्र 08 में नूरजहा मेडम घर से इंद्राणी घर होते हुए हुए रजनी घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य 7.39, श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र 10 में हबीबुन्निशा घर से गुस्तफा घर से होते हुए महबूब अली घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य 4.08, श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र 10 में हबीबुन्निशा घर से मुस्तफा घर से होते हुए महबूब अली घर तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य 1.91, श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र 10 में महावीर प्रसाद गोयल घर से दुवेराय साहू घर तक सीसी रोड 3.71, सोनिया पोपट घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य 3.71, गोकुलपुर वार्ड क्र 23 में सोनकर किराना से कुलेश्वर दिवान घर से छात्रावास तक सीसी रोड निर्माण कार्य 7.27, गोकुलपुर वार्ड क्र 23 में गनपति होटल रोड से कांस करते हुए भटगांव चौक शंकर मंदिर तक आरसीसी नाली निर्माण कार्य 4.25, महंत घासीदास वार्ड क्र 12 में श्रीराम चौक से भागवत चौक तक सीसी रोड निर्माण कार्य 6.00 लाख तथा आदि कार्य किया गया।

जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन एक अगस्त से फिर से शुरू होगी हड़ताल

जगदलपुर। जनवरी माह में मेकाज के पीजी, पीजी बोंडेड डॉक्टर, पोस्ट एमबीबीएस बॉन्डेड डॉक्टर्स और इंटर्न के द्वारा स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल की थी। जिसके बाद उन्हें आश्वासन मिला था। लेकिन उनकी मांगे पूरी होता ना देख एक बार फिर से डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल का एलान किया गया है। जिसमें पहले हफ्ते काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे, उसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती है तो 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होगी। इस मामले को लेकर डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजे जाने की बात कही है।

मामले के बारे में छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टरों ने बताया कि 25 जनवरी 2023 को समस्त चिकित्सा विद्यालय के छात्रों ने पीजी, पीजी बॉन्डेड (स्ष्ठ/स्रू) डॉक्टर, पोस्ट एमबीबीएस बॉन्डेड डॉक्टर्स और इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी हेतु शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। मुख्यमंत्री ने उस समय आश्वासन दिया था कि हमारी मांगों पर एक त्वरित निर्णय लिया जाएगा, लेकिन 6 माह के उपरांत भी स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के विषय में शासन की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया।

सरकारी तंत्र की इस अनदेखी ने डॉक्टरों को काफी हतोत्साहित किया है। इसीलिए हम 1 हफ्ते के ब्लैक रिबन के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी मांगों को फिर से शासन प्रशासन तक लेकर जाने की बात कही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर फिर भी शासन हमारी लंबित मांगों पर कोई निर्णय नहीं लेता है तो डॉक्टर्स एक अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। हड़ताल के समय मरीजो को होने वाली परेशानियों के लिए स्वयं शासन जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी शासन ने हमारी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम में शामिल होने बेंगलुरु पहुंचे युवा कांग्रेसी

नगरी। भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के द्वारा 26-28 जुलाई तक बेंगलुरु में राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.वी श्रीनिवास एवं राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लुवरु के नेतृत्व में 'बेहतर भारत की बुनियाद' कार्यक्रम आयोजित हो रही है। जिसमे शामिल होने प्रदेश सचिव नदीम अली,जिला उपाध्यक्ष प्रमोद कुंजाम, अभिषेक बंजारे अन्य साथियों साथ बेंगलुरु पहुँचे। प्रमोद कुंजाम ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश भर से 3,000 से भी अधिक पदाधिकारियों के भाग लिया है। यह आयोजन आजादी के बाद युवा कांग्रेस का सबसे बड़ा संगठनात्मक युवा सम्मेलन कार्यक्रम होने जा रहा है। आज, समाज का हर वर्ग परेशान है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश की जनता से किए गए वादों की लिस्ट लंबी है लेकिन, मिला कुछ नही जनता पूरी तरह से मोदी सरकार से त्रस्त हो चुकी है। इसलिए भारतीय युवा कांग्रेस 2024 के लिए एक राष्ट्रव्यापी युवा सम्मेलन 'बेहतर भारत की बुनियाद' अभियान शुरू करने जा रही है। अब जनता की मुद्दों को लेकर सड़क की लड़ाई युवा कांग्रेस लड़ेगी।

संविदा कर्मचारियों को कार्य में उपस्थित होने के निर्देश जारी

कोरबा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के तहत विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगो के संबंध में अनाधिकृत रूप से निरंतर हड़ताल पर है, जिससे लोकहित/ नागरिक सेवाएं तथा शासकीय कार्य प्रभावित हो रही है और लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा हैं की उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 की कंडिका 15-1 के अनुसार आचरण नियम 1965 का उल्लंघन है। छ ग शासन गृह विभाग सी अनुभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 04/104/गृह.सी/2023 नवा रायपुर अटल नगर 11/07/2023 द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं हेतु छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिनता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा/1 एवं 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एस्मा लागू किया गया है। उक्त जारी सूचना उपरांत संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर एस्मा अंतर्गत कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए संभाग स्तरीय कार्यशाला आज

कोरबा। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत की संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 28 जुलाई 2023 को बिलासपुर के मोटल बिलासपुर सिटी, नया बस स्टैण्ड के पास तिफरा में प्रातः 11 बजे से आयोजित किया जा रहा है। उक्त कार्यशाला में जिले के समस्त खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत इकाईयों, योजना के लाभार्थी, बैंक प्रतिनिधि, जिला रिसोर्स पर्सन, जिला अग्रणी बैंक, एवं अधिक से अधिक इच्छुक आवेदक सम्मिलित होंगे। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण एकल उद्यमी, एफ्मीओ, स्वसहायता समूह एवं सहकारिता को बैंक के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी दिया जाना है। इस योजना के तहत् नवीन एवं मौजूदा दोनों उद्यमी को पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख तक छूट का प्रावधान है। हितग्राही स्वयं का योगदान 10 प्रतिशत एवं शेष राशि बैंक से ऋण दिया जाएगा।

बिलासपुर-नागपुर सेक्शन में चलेगा इंटरलॉकिंग का काम

बिलासपुर। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के लिए हावड़ा-मुंबई मेन लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत बिलासपुर-नागपुर सेक्शन में तीसरी लाइन में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 28 जुलाई 09.00 बजे से दिनांक 29 जुलाई को 03.00 बजे तक अर्थात 18 घंटे का किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरुप कुछ गाड़ियों को रद्द किया जा रहा है। दिनांक 28 जुलाई को रायपुर से चलने वाली 08707 रायपुर-दुर्ग मेमू पैसेंजर स्पेशल। दिनांक 28 जुलाई को दुर्ग से चलने वाली 08708 दुर्ग-रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल। दिनांक 28 जुलाई को रायपुर से चलने वाली 08709 रायपुर-डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल। दिनांक 29 जुलाई को डोंगरगढ़ से चलने वाली 08710 डोंगरगढ़- रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल। दिनांक 28 जुलाई को रायपुर से चलने वाली 08729 रायपुर -डोंगरगढ़ मेमू पैसेंजर स्पेशल। दिनांक 29 जुलाई को डोंगरगढ़ से चलने वाली 08730 डोंगरगढ़- रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी ।

पांच साल से बंद है बॉक्साइट खदान, रोजी-रोटी की समस्या

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के एकमात्र दलदली क्षेत्र की बॉक्साइट खदान बीते 5 साल से बंद है। खदान बंद होने के कारण क्षेत्र के करीब 2 हजार से अधिक ग्रामीण मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट है। कवर्धा ट्रांसपोर्ट यूनियन की 500 से अधिक वाहन मालिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों के कारण सीधे 32 गांव के ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। इसी समस्या को लेकर गुरुवार को कवर्धा के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को कबीरधाम ट्रक वाहन संघ ने जिले में शीघ्रता से बॉक्साइट उत्खनन और परिवहन शुरू करने के लिए अनुरोध किया है। कवर्धा के न्यू सर्किट हाउस में जिले के विभिन्न संगठनों, संघ और प्रतिनिधिमंडल से सीधे संवाद किया और सभी की मांग व समस्याओं से रूबरू हुए। इसी प्रकार कवर्धा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जीएसटी संबधित कठिनाई बताई। समस्या दूर करने के लिए आग्रह किया। जिला कोटवार संघ ने उपमुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर अपनी मांग रखी।

जोशी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी

■ सेवानिवृत जज पहुंचे ग्राम ओटेबंद व मलपुरी कला, बुजुर्गों से लिया आर्शीवाद

दुर्ग। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विगत 9 सालों के दौरान चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए सेवानिवृत जज अग्रलाल जोशी अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ओटेबंद व मलपुरी कला पहुंचे। उन्होंने मलपुरी कला के भाजपा कार्यकर्ता टीकम साहू का गले में गमछा डालकर स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर बड़े-बुजुर्गों से आर्शीवाद लेते हुए उनकी समस्याओं को सुना।

जनसेवा का भावना को लेकर सेवानिवृत जज अग्रलाल जोशी अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर रहे है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी क्षेत्र

के लोगों तक पहुंचा रहे है ताकि इन योजनाओं का लाभ वे आसानी से उठा सकें। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के स्थायी आमंत्रित सदस्य व सेवानिवृत जज अग्रलाल जोशी मलपुरी कला पहुंचे पर उन्होंने सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ता टीकम साहू के चाय की दुकान पर पहुंचे और गले में गमछा डालकर उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री जोशी आम लोगों से मुलाकात करने व उनकी समस्याओ को जानने के लिए निकल पड़े और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बड़े - बुजुर्गो से आर्शीवाद लिया। जनसंपर्क अभियान के अपने अगले पड़ाव में श्री जोशी ग्राम ओटेबंद पहुंचे और वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा विगत 9 सालों में किए गए जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए वहां की जनता को बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना / मुद्रा योजना, मोर आवास मोर अधिकार, किसान योजना, नल जल योजना, जनधन योजना फसल बीमा योजना, उज्जवला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्टैण्डअप इंडिया, आयुष्मान भारत, वंदे भारत मिशन सहित अन्य योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है जिसका वे आसानी से लाभ उठा सकते है। अरबो-खरबो रूपये खर्च कर भारत को समृद्ध बनाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है और आगे भी रहेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की खामियों को लेकर जनता के बीच जाकर सघल जनसपंर्क अभियान कर रहे है। 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आएगी और कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार का सफाया होना तय है। श्री जोशी हर दिन किसी ने किसी गांव, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत व नगर पालिका के साथ नगर निगम के वार्डों में जाकर आम जनता की समस्याओं से रुबरु हो रहे है और उनके सुख - दुख में भी शामिल हो रहे है। उन्होंने ताउम्र न्याय की सेवा की, अब जनसेवा के लिए मैदान में उतरे है। इस उम्र में जब सेवानिवृति के बाद लोग घर बैठ जाते हैं, उत्साह खो बैठते हैं, तो वहीं अग्रलाल जोशी का उत्साह देखते बनता हैं।

महापौर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक हुई

कोरबा। महापौर राजकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में नगरपालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित एम.आई.सी. कक्ष में बुधवार को मेयर इन काउंसिल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरपालिक निगम कोरबा के मेयर इन काउंसिल सदस्यों द्वारा विभिन्न जनोपयोगी विकास व निर्माण कार्यो से जुड़े हुये मुद्दों पर चर्चा करते हुये प्रस्तुत प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया।

नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में मेयर इन काउंसिल की बैठक में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विषयों के साथ-साथ मोहन लाल मिश्रा सेवानिवृत्त सहायक ग्रेड़ 03 के प्रकरण के संबंध में, इंडियन आयल द्वारा निर्मित इंडियन आयल उपवन को हस्तांरित करने के संबंध में, पं. दीनदयाल उपाध्याय व्यावसायिक काम्पलेक्स भवन/हाल को लीज पर आबंटन के संबंध में, रामपुर में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन के भू-तल पर स्थित कैंटीन को मासिक किरायेदारी पर आबंटन के संबंध में, नगर पालिक निगम कोरबा के वाहन चालकों के समयवृद्वि के संबंध में, एस.ई सी.एल. मानिकपुर उप क्षेत्र में जलआपूर्ति पाईप लाईन बिछाने के कार्य के संबंध में आवश्यक चर्चा हुई। बैठक में एम.आई. सी सदस्य उपस्थित रहे संतोष राठौर, सुनील पटेल, कृपा राम साहू, सुनिता राठौर, मस्तूल सिंह कंवर, प्रदीप राय, पालू राम साहू, सपना चौहान, रोपा तिर्की, सुरति कुलदीप निगम अधिकारी अपर आयुक्त खंजाची कुम्हार, उपायुक्त पवन वर्मा, बी.पी.त्रिवेदी, अधीक्षण अभियंता, एम.के.वर्मा, कार्यपालन अभियंता ए.के.शर्मा, मनोरंजन सरकार, भूषण उरांव, विनोद शांडिल्य, एन.के.नाथ, अखिलेश शुक्ला, तपनयोगी तिवारी, प्रकश चन्द्रा, स्वास्थय अधिकारी डॉ. संजय तिवारी, संपदा अधिकारी अशोक बनाफर, सहायक अभियंता राकेश मसीह, सहायक कार्यालय अधीक्षक रामेश्वर सिंह कंवर आदि उपस्थित थे।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

इंदौर में 30 को रहेंगे अमित शाह, कमलनाथ और कन्हैया

इंदौर। भोपाल में मध्य प्रदेश के नेताओं की लगाम कसने के बाद केंद्रीय गृहमंत्री और विधानसभा चुनाव में मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ की कमान संभालने वाले अमित शाह रविवार यानी 30 जुलाई को बूथ कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। उनका मकसद कार्यकर्ताओं को संदेश देना है कि हम सिर्फ नेताओं के भरोसे नहीं हैं। चुनाव जिताने की असली ताकत कार्यकर्ता होते हैं। मध्यप्रदेश में मैदानी कार्यकर्ताओं का प्रदेश के बड़े नेताओं से नाराज होने का फीडबैक लगातार केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच रहा है। इसी के बाद दिल्ली के नेताओं की प्रदेश में सक्रियता बढ़ी है। रविवार को ही इंदौर में कांग्रेस का भी बड़ा आयोजन है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मध्यप्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ आदिवासी महापंचायत के माध्यम से आदिवासी युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कमलनाथ महिला कांग्रेस के आयोजन में भी शामिल होंगे।

30 जुलाई को मणिपुर जा सकते हैं I.N.D.I.A के सांसद

नई दिल्ली। मणिपुर के मुद्दे पर सदन में खूब हंगामा चल रहा है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से मणिपुर पर संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है कि विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के सांसद 30 जुलाई को हिंसा प्रभावित राज्य मणिपुर का दौरा कर सकते हैं। वहीं मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। संजय राउत ने प्रधानमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीते आठ दिनों से विभिन्न राजनीतिक पार्टियां पीएम मोदी का ध्यान मणिपुर के मुद्दे की तरफ लाने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि यह राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। मणिपुर जल रहा है और लोग मर रहे हैं। मणिपुर की आग अन्य राज्यों में भी फैल सकती है। हम प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हैं कि वह आगे आकर इस मुद्दे पर बोलें। हम उन्हें जवाब नहीं देंगे और सिर्फ उनकी बात सुनेंगे। खरगे ने कहा कि सदन में कामकाज हो रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और बयान जारी करें।

अजित पवार ने एनसीपी चुनाव चिन्ह पर ठोका दावा

मुंबई। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को कहा कि चुनाव आयोग ने एक पत्र भेजकर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के गुट द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न पर दावा करने पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी है, जिसका वे जवाब देंग।। हालांकि, अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि अजित पवार के नेतृत्व में दो जुलाई को एनसीपी में विभाजन हुआ था और वह एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के रूप में आठ अन्य एनसीपी विधायकों के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए थे। सरकार में अजित को उपमुख्यमंत्री पद जबकि आठ अन्य विधायकों को मंत्री पद प्रदान किया गया था। अब अजित पवार गुट ने पार्टी चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। अजित पवार गुट ने चुनाव आयोग को सूचित किया है कि उन्हें 30 जून, 2023 को एक प्रस्ताव के माध्यम से पार्टी के विधायी और संगठनात्मक विंग के सदस्यों ने भारी बहुमत से हस्ताक्षर करके एनसीपी प्रमुख चुना था।

दिल्ली अध्यादेश पर जगन की पार्टी देगी एनडीए को समर्थन

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए लाया जा रहा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (संशोधन) बिल, 2023 संसद के दोनों सदनों से आसानी से पास हो सकता है। लोकसभा में एनडीए का बहुमत है लेकिन राज्यसभा में एनडीए को परेशानी हो सकती थी लेकिन अब एक पार्टी ने एनडीए की उस परेशानी को भी दूर कर दिया है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के बिल को अपना समर्थन दे सकती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने इसकी जानकारी दी है।वाईएसआरसीपी के नेता वी विजयसाई रेड्डी ने बताया कि उनकी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव और दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर सरकार का समर्थन करेगी। पार्टी के सांसदों को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। नौ सांसदों वाली बीजू जनता दल भी एनडीए सरकार का समर्थन कर सकती है। हालांकि अभी तक नवीन पटनायक ने अपना रुख साफ नहीं किया है।

मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना

नईदिल्ली। विपक्षी नेता मणिपुर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ और साथ ही हिंसाग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य पर दोनों सदनों में बयान नहीं देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ संसद में हर दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ओर जहां संसद में मणिपुर को लेकर विपक्षी दल नरेंद्र मोदी के बयान की मांग कर रहे हैं। वहीं, प्रधानमंत्री आज राजस्थान से इंडिया को लेकर कड़ा प्रहार किया है। इसी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। खड़गे ने कहा कि सदन चल रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि पीएम वहां आएं और बयान दें लेकिन वे राजस्थान में राजनीतिक भाषण दे रहे हैं और चुनाव की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वे वहां जा सकते हैं तो क्या आधे घंटे के लिए सदन में आकर बयान नहीं दे सकते? इसका मतलब है कि लोकतंत्र में उनकी कोई रुचि नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। वे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं करना चाहते, वे संसद का अपमान कर रहे हैं।

राजस्थान में बोले नरेंद्र मोदी- कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान

लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे : प्रधानमंत्री

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के दौरे पर थे। राजस्थान चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। इन सबके बीच राजस्थान के सीकर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मतलब लूट की दुकान और झूठ का बाजार है। इसके साथ ही उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आज का राजस्थान में लाल डायरी के चर्चे हैं। लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे-अच्छे लिपट जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हुए हैं। उन्होंने गहलोत सरकार पर पेपर लीक को लेकर भी निशाना साधा।

मोदी ने कहा कि आप इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने आए हैं। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊँट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान में एक ही गूंज है, एक ही नारा है... जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अच्छी सड़कों के लिए, अच्छे हाईवे के लिए, राज्य के विकास के लिए भाजपा सरकार लगातार पैसे भेज रही है। मोदी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब 10 वर्षों में राजस्थान में टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में एक लाख करोड़ रुपये ही दिए गए थे, बीते 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में चार लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंचाए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है और झूठ का बाजार चलाया है। झूठ की दुकान का सबसे ताजा प्रोजेक्ट है, राजस्थान की %लाल डायरी%। उन्होंने कहा कि कहते हैं इस %लाल डायरी% में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कह रहे हैं कि %लाल डायरी% के पन्ने खुले तो अच्छे-अच्छे निपट जाएंगे। मोदी ने कहा कि

कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस %लाल डायरी% का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा लें, लेकिन ये %लाल डायरी% इस चुनाव में कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है। राजस्थान के युवा काबिल हैं, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहां सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। युवाओं को पेपर लीक माफिया से बचाने के लिए कांग्रेस को हटाना ही होगा।

मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों गरीबों को पक्का घर बनाकर लखपति बनाने की गारंटी किसने दी? -भाजपा सरकार ने। देश के करोड़ों गरीबों को मुफ्त राशन की गारंटी किसने दी? -भाजपा सरकार ने। कोरोना काल में करोड़ों गरीबों को मुफ्त वैक्सीन की गारंटी किसने दी? -भाजपा सरकार ने। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों गरीबों को अस्पताल में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी किसने दी?-भाजपा सरकार ने। जनऔषधि केंद्र में गरीबों को सस्ती दवाइयों की गारंटी किसने दी? -भाजपा सरकार ने। गरीब का बच्चा भी डॉक्टर-इंजीनियर बन सके, अंग्रेजी ना आने की वजह से पीछे ना रह जाए, इसके लिए मातृभाषा में पढ़ाई की गारंटी किसने दी? -भाजपा सरकार ने।

किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है, आज उनके दुख-दर्द को समझने वाली सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर है। राजस्थान के सीकर में उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने देश के करोड़ों किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी जारी किया। मोदी ने कहा कि आज यहां से देश के करोड़ों किसानों के पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन केंद्रो से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि वीरों की भूमि शेखावटी से देश के लिए अनेक विकास परियोजनाओं को शुरू करने का अवसर मिला है।

मोदी ने कहा कि आज देश में सवा लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरूआत की गई है। आज 1.5 हजार से अधिक, क्क के लिए हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का लोकार्पण भी हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के अलग-अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य स्कूल का उपहार भी मिला है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर किसानों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मोदी ने कहा कि आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम, मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। इसलिए सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

राहुल गांधी का आरोप- सिर्फ सत्ता चाहती है भाजपा

मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे पीएम

नईदिल्ली। मणिपुर को लेकर देश की राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने है। सड़क से लेकर संसद तक लगातार वार पलटवार की राजनीति चल रही है। इन सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए राहुल गांधी का वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में राहुल गांधी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर मामले को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे हैं।

अपने वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर के लिए क्या कर रहे हैं? वे मणिपुर के बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है। वो जानते हैं कि उनकी ही विचारधारा ने मणिपुर को जलाया है। राहुल ने आरोप लगाया कि भाजपा-आरएसएस सिर्फ सत्ता चाहती है और सत्ता पाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए ये मणिपुर को जला देंगे, सारे देश को जला देंगे। इनको देश के दुख और दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा-आरएसएस और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस की विचारधारा- संविधान की रक्षा, देश को जोड़ने और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ने की है। वहीं भाजपा-आरएसएस चाहती है कि कुछ चुनिंदा लोग यह देश चलाएं और देश का सारा धन उन्हीं के हाथ में हो। उन्होंने कहा कि आपके दिल में देशप्रेम है। जब देश को चोट लगती है, देश के किसी नागरिक को चोट लगती है तो आपके दिल को भी चोट लगती है। आप उदास हो जाते हैं। मगर भाजपा-आरएसएस के लोगों को कोई दु:ख नहीं, कोई दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि ये हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रहे हैं।

आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में मणिपुर को लेकर हंगामा जारी है। लगातार विपक्षी

दल इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि वह चर्चा को तैयार है। हालांकि, विपक्षी दल यह भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को इस पर संसद में बयान देना चाहिए। मणिपुर मामले को लेकर ही विपक्षी दलों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है।

मोदी के लाल डायरी वाले बयान पर गहलोत का पलटवार

जयपुर। सीकर में मोदी ने लाल डायरी के बहाने अशोक गहलोत की सरकार पर निशाना साधा। इसके बाद गहलोत की ओर से भी पलटवार किया गया है। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को लाल डायरी, जो डायरी कपोल कल्पित है उसपर बात करने की बजाय लाल टमाटर, लाल सिलेंडर, महंगाई से हुए लोगों के लाल चेहरों पर बात करनी चाहिए...आने वाले वक्त में जनता भाजपा को लाल झंडी दिखाएगी। उन्होंने कहा कि सुना है पीएम ने सीकर में लाल डायरी पर भाषण दिया था। पीएम का पद गरिमा रखता है। देश भर में आईटी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। क्या वे उनसे डायरी के बारे में जानकारी नहीं जुटा सकते?...क्या वे इतने परेशान हैं? राजस्थान को निशाना बनाया जा रहा है- कि यहां अत्याचार है, कि यहां कोई कानून-व्यवस्था नहीं है. सबसे ज्यादा छापेमारी राजस्थान में हुई है। उन्होंने कहा कि तीन महीने में चुनाव होने हैं। वे परेशान हैं क्योंकि वे लोगों का मूड देख सकते हैं। इसलिए वे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. लाल डायरी उनमें से एक है।

खेल
प्रमुख समाचार

भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने नीदरलैंड के साथ ड्रॉ खेला

बार्सीलोना। भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग 2022 .23 खिताब जीतने वाली नीदरलैंड टीम को स्पेनिश हॉकी महासंघ की सौंवी वर्षगांठ पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में 1 . 1 से ड्रॉ पर रोका। भारत को पहले मैच में स्पेन ने हराया था लेकिन भारतीय टीम ने दूसरे मैच में प्रभावी प्रदर्शन किया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने भारत के लिये एकमात्र गोल 12वें मिनट में किया जबकि डच टीम के लिये जैस्पर ब्रिंकमैन ने 40वें मिनट में बराबरी का गोल दागा। भारत ने शुरूआत से ही आक्रामक खेल दिखाया लेकिन पहला पेनल्टी कॉर्नर डच टीम को मिला जिस पर गोल नहीं हो सका। भारत को 12वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर को हरमनप्रीत ने गोल में बदला। हार्दिक सिंह से मिली गेंद को गोल के भीतर डालने में उन्होंने कोई चूक नहीं की।

दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन गोल नहीं हो सका। भारत के लिये पीआर श्रीजेश की जगह उस समय खेल रहे गोलकीपर कृशन पाठक ने प्रभावी प्रदर्शन किया। डच गोलकीपर मौरिटिस विस्सेर ने भी भारतीयों को गोल नहीं करने दिये। तीसरे क्वार्टर की शुरूआत में दोनों टीमों को एक एक पेनल्टी कॉर्नर मिला। श्रीजेश ने मैदान पर लौटने के बाद डच टीम को गोल से वंचित रखा। आखिरकार ब्रिंकमैन का अनुभव डच टीम के काम आया जिन्होंने पेनल्टी कॉर्नर पर बराबरी का गोल किया। आखिरी क्षणों में भारत ने हरमनप्रीत की अगुवाई में जवाबी हमला किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार फिर से धड़ाम सेंसेक्स 440 अंक टूटा

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित रुझानों और इंट्रा-डे ट्रेड में उतार-चढ़ाव के बाद सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में फ्रंटलाइन सूचकांक सेंसेक्स लगभग 440 अंक लुढ़का। निफ्टी में भी 118 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा उम्मीद के मुताबिक 25 बीपीएस दर बढ़ोतरी से भी निवेशकों की धारणा पर असर पड़ा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 440.38 अंक यानी 0.66 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 66,266.82 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 66,984.17 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 66,060.74 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी 118.40 अंक यानी 0.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की। निफ्टी दिन के अंत में 19,659.90 अंक पर बंद हुआ।

नेटवेब टेक का लिस्टिंग वाले दिन दोगुना हुआ पैसा

नईदिल्ली। सुपर कंप्यूटर बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी नेटवेब टेक का शेयर 27 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो गया है। बीएसई पर शेयर 942.5 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ है। शेयर ने लिस्टिंग के दिन ही पैसा डबल कर लिया है। एक्सचेंज आंकड़ों के मुताबिक शेयर 500 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर 947 रुपए के भाव पर लिस्ट हुआ है। यानी शेयर करीब 90% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। लिस्टिंग के पहले भी इसे निवेशकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। यही वजह रही कि अंतिम दिन आईपीओ 90 गुना से ज्यादा भरकर बंद हुआ था। नेटवेब टेक का 631 करोड़ रुपये का आईपीओ 17-19 जुलाई तक खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों को तगड़ा रिस्पांस मिला था। क्वालिफाईड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा सबसे अधिक 220.69 गुना भरा था।

फॉक्सकॉन तमिलनाडु में 200 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी

नईदिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन की सब्सिडियरी कंपनी फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट तमिलनाडु में 200 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है। कंपनी के के सीईओ ब्रांड चेंग और अन्य कंपनी प्रतिनिधियों ने पिछले हफ्ते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और अन्य सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में निवेश पर चर्चा की गई थी। रॉयटर्स ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि एफआईआई ने राज्य के अधिकारियों के साथ शुरुआत में राज्य में रू. 180 मिलियन से रू. 200 मिलियन का निवेश करने की योजना साझा की है। ताइवान स्थित कंपनी का 2024 तक प्लांट पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। प्लांट पूरा होने के बाद और निवेश की उम्मीद है। हालांकि तमिलनाडु में इस निवेश को लेकर अभी अंतिम निर्णय होना बाकी है। फॉक्सकॉन इंडस्ट्रियल इंटरनेट संचार, मोबाइल नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग उपकरण बनाता है।

नेस्ले का जून तिमाही का मुनाफा 36.86 प्रतिशत बढ़ा

नयी दिल्ली। रोजमर्रा के उपभोग का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया लि. का 30 जून, 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही का शुद्ध लाभ 36.86 प्रतिशत बढ़कर 698.34 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी जनवरी-दिसंबर वित्त वर्ष का अनुपालन करती है। इससे पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी ने 510.24 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में नेस्ले इंडिया ने कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल बिक्री 15.02 प्रतिशत बढ़कर 4,619.50 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। एक साल पहले समान तिमाही में यह 4,015.98 करोड़ रुपये रही थी। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का कुल खर्च 11.07 प्रतिशत बढ़कर 3,743.15 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 3,369.81 करोड़ रुपये रहा था।

पूंजी बाजार में बढ़ रहा विदेशी निवेश

(गतांक से आगे...)

प्रह्लाद सबनानी

पिछले लगभग 10 वर्षों के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर में अतुलनीय सुधार हुआ है। हाल ही के वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे को विकसित करने में बहुत अधिक काम सम्पन्न हुआ है और अब भारतीय बुनियादी ढांचा विकसित देशों के बुनियादी ढांचे से टक्कर लेता दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार के प्रयास अब विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने के लिए भी किए जा रहे हैं। ऑटो उद्योग के लिए 'चिप' निर्माण करने वाली इकाईयों को अब भारत में ही स्थापित किया जा रहा है, जबकि अभी तक भारत में चिप का आयात किया जा रहा था। सुरक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न उत्पादों का आयात किया जाता था परंतु अब भारत में ही विनिर्माण इकाईयों की स्थापना की जा रही हैं और भारत इस क्षेत्र में आत्म निर्भर बनता जा रहा है। मोबाइल विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भारत में हुई है, भारतीय ऑटो उद्योग तो अब विश्व में नम्बर एक उद्योग बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। विश्व की कई बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी विनिर्माण इकाईयां भारत में स्थापित करती जा रही हैं। कई देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते सम्पन्न हो रहे हैं तथा कुछ देशों के साथ विदेशी व्यापार भी भारतीय रुपए में सम्पन्न किया जाने लगा है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है। रूस, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि कई देशों के साथ रुपए में विदेशी व्यापार प्रारम्भ हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत बढ़ रही है। इससे भारत में विदेशी निवेश के लिए माहौल बन रहा है। साथ ही इस सबका प्रभाव यह हो रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत से

अधिक की दर से आगे बढ़ रही है और आगे आने वाली कई दशाब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में इसी प्रकार की तेजी बने रहने की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। स्टॉक बाजार देश की अर्थव्यस्था का आईना रहता है। भारत में स्टॉक बाजार के तेज गति से बढ़ने का आशय भी यही है कि भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर आकर्षक बनी रहेगी।

आगे आने वाले समय में भारतीय स्टॉक बाजार में वृद्धि दर और भी तेज होने की सम्भावना इसलिए भी बलवती होती जा रही है क्योंकि आज भी भारतीय स्टॉक बाजार में खुदरा निवेशकों की पैठ बहुत कम है। 140 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले देश में केवल 14 करोड़ डीमैट खाते खोले जा सके हैं। कोरोना खंडकाल से पहले भारत में डीमैट खातों की संख्या केवल 4 करोड़ के आसपास थी और कोरोना खंडकाल के दौरान लगभग 7-8 करोड़ नए डीमैट खाते खोले गए हैं। हालांकि अब खुदरा निवेशकों का रुझान तेजी से स्टॉक बाजार की ओर बढ़ रहा है। डिपोजिटरी आंकड़ों के अनुसार खुदरा घरेलू निवेशकों ने भारतीय स्टॉक बाजार में 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है।

एक और महत्वपूर्ण कारण जिसके चलते भारतीय स्टॉक बाजार में तेजी बरकरार रहने की सम्भावना है वह है भारत में जीओ पालिटिकल टेंशन तुलनात्मक रूप से कम है, जबकि अन्य देशों के आपसी सम्बंध बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। यूरोपीय देश आपस में लड़ रहे हैं तो इधर रूस एवं यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। चीन के भी अपने पड़ोसी देशों से सम्बंध बहुत अच्छे नहीं हैं। साथ ही, भारत में राजनैतिक स्थिरता है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में ही मानी जाती है। भारतीय राज्य भी अब आर्थिक विकास के मामले में आपस में प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे हैं। पहले केवल गुजरात राज्य को ही तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था कहा जाता था। परंतु, अब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा आदि राज्य भी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं इनमें से कुछ राज्यों ने तो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर का बनाने की ओर अपने कदम बढ़ा दिये हैं। 19वीं शताब्दी यदि यूरोप की थी और 20वीं शताब्दी यदि अमेरिका की थी तो अब 21वीं शताब्दी भारत की होने जा रही है।

छोटे दलों के पीछे क्यों भाग रहे हैं बड़े दल

नदीम

पहली नजर में देखें तो बीजेपी के सामने ओमप्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी की कोई बिसात नहीं है। यह भी याद होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से गठबंधन खत्म करने के बाद ओमप्रकाश राजभर ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। फिर भी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद राजभर से मुलाकात की और उन्हें बीजेपी के साथ लाने के लिए मनाया। राजभर से पहले अमित शाह ने पिछले महीने बिहार की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी से भेंट कर उनकी एनडीए में वापसी पक्की कराई। राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की जो गोलबंदी हो रही है, उसमें भी अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग समूहों पर पर असर रखने वाले दलों को साथ लेने की हरसंभव कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय राजनीति में यह बदलाव आया कैसे? दरअसल, नब्बे के दशक में जब मंडल-कमंडल की राजनीति का उभार शुरू हुआ तो धार्मिक गोलबंदी के साथ-साथ जातीय गोलबंदी का भी रास्ता खुलना शुरू हुआ। यहीं से अलग-अलग जातियों और उपजातियों के बीच राजनीतिक नेतृत्व पैदा होने शुरू हुए और छोटे-छोटे राजनीतिक दल अस्तित्व में आने लगे। इसका बड़ा असर खास तौर पर यूपी और बिहार की राजनीति में दिखना शुरू हुआ। यूपी में छोटे दलों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जिस राज्य की पॉलिटिक्स अब तक बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी जैसे बड़े जनाधार वाले दलों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, वहां अब अपना दल, महान दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, बहुजन आजाद पार्टी, जनवादी सोशलिस्ट जैसे दलों का न केवल दखल बढ़ा है बल्कि उन्होंने बड़े दलों को अपनी शर्तों पर झुकने को मजबूर कर दिया है। बीजेपी को यूपी में निषाद पार्टी को साथ बनाए रखने के लिए न केवल उसके अध्यक्ष डॉ संजय निषाद को विधान परिषद भेजना पड़ा बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी के टिकटों का कोटा भी तय करना पड़ा था। अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में मंत्री तो बनीं ही, उनके पति को भी यूपी में एमएलसी बनाकर उनके लिए योगी सरकार में मंत्री पद सुरक्षित किया गया। राजभर को फिर से एनडीए में लाने के लिए बीजेपी ने उनके साथ तल्खी भुला दी। यूपी के 2017 के विधानसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी और योगी सरकार में हिस्सेदार भी बनी। लेकिन 2022 चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के पाले में चली गई थी। वहीं, 2022 चुनाव में जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बातचीत को तैयार नहीं हुई थी, वह महान दल, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और अपना दल कमेरावादी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी। ये छोटे दल जिन जातियों की नुमाइंदगी करते हैं उनकी आबादी को अगर राज्य की कुल आबादी की कसौटी पर कसा जाए तब तो वह बहुत कम दिखेगी। लेकिन इन पार्टियों का जनाधार जिस जाति के लोग हैं, वे राज्य के कुछ खास जिलों में केंद्रित हैं। इसलिए ये पार्टियां उन जिलों के चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखती हैं। यूपी जैसा ही हाल बिहार का भी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बिहार में महादलित समाज की नुमाइंदगी करता है। बिहार की राजनीति में महादलित मतदाता इतनी संख्या में हैं कि वहां के चुनाव को प्रभावित करते हैं। लिहाजा इनकी मांग बनी रहती है। इसलिए बिहार में जीतन राम मांझी हर चुनाव के वक्त अपनी सुविधा के अनुसार 'पार्टनर' बदलते रहते हैं। नीतीश, लालू और बीजेपी, जिसके साथ वह जाना चाहते हैं, उनके दरवाजे खुल जाते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का आत्मघाती गोल

अजय सेटिया

विपक्ष ने लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसका गिरना तय है क्योंकि एनडीए के 331 सांसद हैं, टीडीपी के 3 और जेडीएस का एक सांसद भी एनडीए के साथ हैं। दूसरी तरफ 210 सांसद बचते हैं, अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 210 वोट नहीं पड़ते तो विपक्ष का यह दावा गलत साबित हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन मोदी के खिलाफ खड़ा हो चुका है। विपक्ष, जिसे अब वे सदन से बाहर इंडिया कह रहे हैं, उसके लोकसभा में सिर्फ 142 सांसद हैं, टीआरएस के 9 सांसद भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देंगे। 9 अन्य सांसदों पर भी विपक्ष को भरोसा है कि वे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट करेंगे।

वाईएसआर कांग्रेस-22, बीजू जनता दल-12, और बसपा-9 सांसद भी तटस्थ हैं, लेकिन इन तीनों दलों के 43 सांसदों के विपक्ष के साथ वोट किए जाने की संभावना अभी तक नजर नहीं आती। इसलिए यह तय है कि पटना और बेंगलुरु बैठकों से उसने जो माहौल बनाने की कोशिश की है, उसकी हवा अविश्वास प्रस्ताव से निकल जाएगी।

विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर बड़ी राजनीतिक गलती कर ली है। वह मणिपुर के मुद्दे पर बात करना चाहता था, और सरकार उसके लिए तैयार थी। गृहमंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को चिट्ठी लिख कर कहा था कि विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर जितनी लंबी बहस करना चाहता है, करे, सरकार उसके लिए तैयार है, लेकिन आप बहस करिए। जबकि विपक्ष बहस के बजाए हंगामा कर रहा था।

विपक्ष की जिद्द यह थी कि पहले प्रधानमंत्री दोनों सदनों में मणिपुर पर बयान दें, फिर बहस होगी। राज्यसभा में तो बयान के बाद सवाल उठाने के नियम हैं, लेकिन लोकसभा में तो यह नियम ही नहीं है कि मंत्री या प्रधानमंत्री के बयान के बाद उस पर स्पष्टीकरण मांगा जाए। विपक्ष के नेता सदन को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, जबकि सदन नियमों से चलता है।

विपक्ष का राजनीतिक दृष्टिकोण भी इतना कमजोर क्यों हो गया है कि अपना नफा नुकसान ही नहीं देख पा रहा। वैसे भी अगर मणिपुर पर बहस होती, तो प्रधानमंत्री मोदी बहस में दखल देते हुए अपना बयान देते ही, तब आप जितने चाहे सवाल दाग सकते थे। वह संसद सत्र के पहले दिन पत्रकारों के सामने मणिपुर की शर्मनाक घटना की न सिर्फ निंदा कर चुके हैं, बल्कि देश को आश्वासन भी दे चुके हैं कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दो महिलाओं को नग्न करके पीटने का वीडियो सामने आने के बाद सात लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं।

किसी भी प्रदेश में क़ानून व्यवस्था के मुद्दे पर बहस करनी हो तो वह गृह मंत्रालय के अधीन ही आती है। विपक्ष के नेता नियम पर भी अड़े थे कि फलां नियम में बहस होनी चाहिए, फलां में नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी भी नियम में बहस करने को तैयार थी, लेकिन मणिपुर पर बहस के बजाए मोदी को कटघरे में खड़ा करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देकर विपक्ष ने गलती कर दी है।

अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी होगा, अविश्वास प्रस्ताव पर दो या तीन दिन की बहस होगी। भाजपा के सांसद ज्यादा हैं, तो बोलने का मौक़ा भी ज्यादा उन्हीं को ही मिलेगा। अब बहस सिर्फ मणिपुर पर नहीं होगी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटनाओं पर भी होगी, जहां महिलाओं के खिलाफ करीब करीब मणिपुर जैसी ही घटनाएं हुई हैं। राजस्थान में तो सरकार के मंत्री राजेन्द्र गुढा ने ही कांग्रेस को यह कह कर कटघरे में खड़ा कर दिया था कि मणिपुर से पहले अपना घर तो संभालों, अपने गिरेबान में तो झांको।

बंगाल में पंचायत चुनावों में मारे गए निरपराध कांग्रेस, वामपंथी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं की हत्याओं की भी चर्चा होगी। पंचायत चुनावों में 46 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बहस में जब यह मुद्दा उठाया जाएगा, तो कांग्रेस, कम्युनिस्ट और एआईएमआईएम किसके साथ खड़े होंगे। क्या वे तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े हो पाएंगे, जो इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। अभी 18 जुलाई को जब सीताराम येचुरी का ममता बनर्जी का हाथ पकड़ते हुए फोटोवायरल हुआ था, तो बंगाल के उन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में हंगामा किया, जिनके पारिवारिक सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस की हिंसा में अपनी जान गंवाई है।

अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि न सिर्फ विपक्ष के आपसी मतभेद खुल कर सामने आयेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को सदन में खुल कर बोलने का मौक़ा दे दिया है। वह दो घंटे बोलेंगे और धोकर रख देंगे। अविश्वास प्रस्ताव का हो हल्ला तो बहुत होगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने पहली हार कबूल कर ली है, क्योंकि अब मोदी तो आखिर में बोलेंगे, वह शुरू में तो बोलेंगे नहीं। वह तो बहस का जवाब देंगे।

मोदी के विजन पर मोदी विरोधियों को कितना भी संशय हो, मोदी के विजन पर उनके समर्थकों को पूरा भरोसा है। खुद विपक्ष ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मोदी को अपनी नौ साल की उपलब्धियां गिनाने का स्वर्णिम अवसर उपलब्ध करवा दिया है। भाजपा का दावा है मोदी ने पिछले नौ साल में वह करके दिखाया है, जो 65 साल से नहीं हुआ था। देश ने आर्थिक मोर्चे पर बेमिसाल तरक्की की है, इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की की है। सड़कें, ट्रेन, हवाई अड्डे, पोर्ट, भारत एकदम बदल गया है। साईंस और विज्ञान के क्षेत्र में भी बेमिसाल तरक्की की है। कोरोना के दौरान भारत ने मेडिकल क्षेत्र में पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं।

बहस के दौरान एनडीए के सांसद उन उपलब्धियों को गिनाएंगे और बताएंगे कि मोदी ने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, आज पूरी दुनिया में इंडिया की पहचान मोदी से हो रही है। विश्व के बड़े बड़े नेता उनके विजन और कामों का लोहा मान रहे हैं, यह देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आप उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर देश और दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हो।

अब मुद्दा मणिपुर नहीं रहा, अब मुद्दा अविश्वास प्रस्ताव हो गया है, मणिपुर पर बहस न करके, और अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने साबित कर दिया कि वह इतने दिन तक मणिपुर की शर्मनाक घटना को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष शायद अपनी एकता का अहसास करवाना चाहता है। यह अहसास वह दिल्ली अध्यादेश के बिल पर भी करवा सकता था, जिसे केबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर मोदी को विधानसभा चुनावों में प्रचार का मौक़ा दे दिया है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर उनके जवाब को देश भर के चैनलों पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है, जो देश को प्रभावित करने की क्षमता रखता हो। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को कौन सुनेगा। सोनिया गांधी क्या और कितना बोलेंगी। समाजवादी पार्टी के पास कोई बोलने वाला नहीं है, राजद-जेडीयू में कोई बोलने वाला नहीं, लेफ्ट में भी कोई असरदार बोलने वाला नहीं। विपक्ष के बोलने वाले सभी नेता लोकसभा का चुनाव हार गए थे, वे सब अब राज्यसभा में हैं, और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश होता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

दव्युपनिषद्

यह उपनिषद् अथर्ववेदीय परम्परा के अन्तर्गत आती है। देवगणों और महादेवी के बीच प्रश्नोत्तर के रूप में यह उपनिषद् विवेचित है। इसमें सर्वप्रथम चित शक्ति के सर्वात्म रूप और सर्वधारक रूप का वर्णन किया गया है। तदुपरान्त देवों द्वारा देवी की स्तुति है। इसके बाद क्रमशः आदिविद्या का उद्धार, आदिविद्या की महिमा, भुवनेशी एकाक्षर मन्त्र, महाचण्डी नवाक्षर विद्या तथा अन्त में इस विद्या की फलश्रुति वर्णित हुई है। यह उपनिषद् वैसे तो छोटी है; परन्तु देवी साधना के तन्त्र मार्ग की दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण उपनिषद् है।

समस्त देवगण देवी के समक्ष उपस्थित होकर प्रार्थना करते हुए बोले- हे महादेवि! आप कौन हैं? कृपा करके बताने का अनुग्रह करें। तदनन्तर उन (देवी) ने उत्तर दिया- हे देवो! मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ। मेरे द्वारा ही यह प्रकृति-पुरुषात्मक विश्व प्रादुर्भूत हुआ है। (अज्ञानियों के लिए) यह मुझसे शून्य (रहित) तथा (ज्ञानियों के लिए) अशून्य (सहित) है। मैं ही आनन्दस्वरूपा एवं आनन्दरहिता हूँ। मैं विज्ञानमयी एवं विज्ञान- विहीना हूँ। निश्चय ही मैं जानने योग्य ब्रह्म एवं ब्रह्म से भी परे हूँ। ऐसा ही अथर्ववेद का यह मंत्र है। मैं ही पञ्चीकृत (पाँच तत्त्वों का सम्मिलित रूप) और अपञ्चीकृत (पाँच तत्त्वों का स्वतंत्र रूप) महाभूत भी हूँ। दृष्टिगोचर होने वाला सम्पूर्ण विश्व भी मैं ही हूँ। वेद (ज्ञान) एवं अवेद (अज्ञान) भी मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ। अजा (प्रकृति) और अनजा (प्रकृति से भिन्न) भी मैं ही हूँ। ऊर्ध्व एवं अधः और अगल-बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों एवं वसुओं के रूप में सर्वत्र सञ्चरणशील हूँ। मैं आदित्यों एवं विश्वेदेवों के रूप में सर्वत्र विचरण किया करती हूँ। मैं ही मित्र तथा वरुण का, इन्द्र एवं अग्नि का तथा दोनों अश्विनीकुमारों का सदैव पालन-पोषण किया करती हूँ। मैं ही सोम, पूषा, त्वष्टा एवं भग को भी धारण करती हूँ। मैं ही त्रिलोकी को आक्रान्त करने के लक्ष्य प्राप्ति हेतु विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले भगवान् विष्णु, ब्रह्मदेव एवं प्रजापति को भी धारण करती हूँ। मैं ही देवताओं को हवि पहुँचाने तथा सावधानी पूर्वक सोमाभिषव करने वाले यजमान के निमित्त हविर्द्रव्यों से सम्पन्न धन को धारण करती हूँ। मैं ही सम्पूर्ण विश्व की अधीश्वरी, उपासकों के लिए धन-प्रदान करने वाली, ज्ञानवती और यजन करने योग्य देवों में प्रमुख हूँ। मैं ही इस विश्व के पितास्वरूप सर्वाधिष्ठानरूप परमात्मा को प्रकट करती हूँ।

क्रमशः ...

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस

ललित गर्ग

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कई प्रजाति के जीव-जंतु, प्राकृतिक स्रोत एवं वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते जीव-जंतु और वनस्पति की रक्षा के लिये विश्व-समुदाय को जागरूक करने के लिये ही इस दिवस को मनाया जाता है। आज चिन्तन का विषय न तो युद्ध है और न मानव अधिकार, न कोई विश्व की राजनैतिक घटना और न ही किसी देश की रक्षा का मामला है। चिन्तन एवं चिन्ता का एक ही मामला है लगातार विकराल एवं भीषण आकार ले रही गर्मी, सिकुड़ रहे जलस्रोत विनाश की ओर धकेली जा रही पृथ्वी एवं प्रकृति के विनाश के प्रयास। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता प्रदूषण, नष्ट होता पर्यावरण, दूषित गैसों से छिद्रित होती ओजोन की ढाल, प्रकृति एवं पर्यावरण का अत्यधिक दोहन- ये सब पृथ्वी एवं पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़े खतरे हैं और इन खतरों का अहसास करना ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का ध्येय है। प्रतिवर्ष धरती का तापमान बढ़ रहा है। आबादी बढ़ रही है, जमीन छोटी पड़ रही है। हर चीज की उपलब्धता कम हो रही है। आक्सीजन की कमी हो रही है। साथ ही साथ हमारा सुविधावादी नजरिया एवं जीवनशैली पर्यावरण एवं प्रकृति के लिये एक गंभीर खतरा बन कर प्रस्तुत हो रहा हैं। जल, जंगल और जमीन इन तीन तत्वों से प्रकृति का निर्माण होता है। यदि यह तत्व न हों तो प्रकृति इन तीन तत्वों के बिना अधूरी है। विश्व में ज्यादातर समृद्ध देश वही माने जाते हैं जहां इन तीनों तत्वों का बाहुल्य है। बात अगर इन मूलभूत तत्व या संसाधनों की उपलब्धता तक सीमित नहीं है। आधुनिकीकरण के इस दौर में जब इन संसाधनों का अंधाधुन्ध दोहन हो रहा है तो ये तत्व भी खतरे में पड़ गए हैं। पिछले दिनों पहाड़ों के शहर शिमला में पानी की भयावह कमी आ गई थी। अनेक शहर पानी की कमी से परेशान हैं। ये सब आजकल साधारण सी बात है। आज हम हर दिन किसी-न-किसी शहर में पीने के पानी की कमी के बारे में सुन सकते हैं।

इस तरह की प्रकृति एवं पर्यावरण से जुड़ी विकराल स्थितियों के प्रति सचेत एवं सावधान नहीं हुए तो भविष्य निश्चित ही खतरे में पड़ेगा। आज जरूरत हमारी पृथ्वी के पर्यावरण को स्वस्थ बनाये रखने की है, उसे संरक्षित करने की है। बहुत चिंता का विषय है कि खुद मनुष्य पृथ्वी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। कितनी विचित्र बात है कि एक आदमी ही ऐसा प्राणी है जिसने सब कुछ पाकर स्वयं को खो दिया है। आप ही बताइये कि कहां खो गया वह आदमी जो स्वयं को कटवाकर भी वृक्षों को कटने से रोकता था? गोचरभूमि का एक टुकड़ा भी किसी को हथियाने नहीं देता था। जिसके लिये जल की एक बूंद भी जीवन जितनी कीमती थी।

आज आवश्यकता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की ओर विशेष दिया जाए, जिसमें मुख्यतरू धूप, खनिज, वनस्पति, हवा, पानी, वातावरण, भूमि तथा जानवर आदि शामिल हैं। इन संसाधनों का अंधाधुंध दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण ये संसाधन धीरे-धीरे समाप्त होने की कगार पर हैं। प्रकृति के संरक्षण को सभी देशों की सरकारों एवं विभिन्न गैर-राजनैतिक संगठनों ने बड़ी गम्भीरता से लिया है और इस पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। ऐसे भी अनेक तरीके हैं जिनमें आम आदमी भी इनके संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। हमें शुद्ध हवा के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है, इसलिये अधिक से अधिक पेड़ लगाने की तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है।

मतभेद कम कर लेना ही इंडिया की सफलता होगी

आनंद पांडे

18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर चुनाव अभी महीनों दूर हैं। कायदे से सरकार और विपक्ष को अभी चुनाव आचार संहिता लागू होने तक संसदीय दायरे में ही अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। पर लोकतंत्र में बारहों मास चुनाव का भूत सवार रहता है। इसी भूत ने कल सत्तारूढ़ दलों और विपक्षी दलों को फिर से पुनर्गठित होने और नए सिरे से मोर्चेबन्दी के लिए बाध्य किया। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन अपने पुराने नाम के साथ ही 38 दलों का एक मोर्चा घोषित हो चुका है तो विपक्षी 26 दलों ने इंडिया के नए और अधिक आकर्षक नाम के साथ खम ठोक दिया है। इंडिया अंग्रेजी के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायन्स का संक्षेपाक्षर है।

इसी के साथ कई चीजें साफ हो गयी हैं। एक तो यह कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की अच्छी कामयाबी और कर्नाटक की भारी जीत के बावजूद अकेले चुनावों में उतरने की सोच भी नहीं पा रही है। पर यदि इंडिया को जीत हासिल करनी है तो इसके घटक दलों में सबसे ज्यादा होमवर्क और प्रदर्शन कांग्रेस को ही करना है। कांग्रेस को अपनी सीटों को कम-से-कम तिगुना करना होगा। अगर कांग्रेस 2024 में अपने आप को साबित करना चाहती है तो भाजपा से कम-से-कम सौ से अधिक सीटें अकेले कांग्रेस को छीननी होंगी। दूसरी बात जो साफ हुई है वह यह कि भाजपा 303 सीटें जीतने के बावजूद 2024 में पूर्ण बहुमत को लेकर आशंकित है। इसलिए वह 38 दलों को जोड़ रही है। अकेले लड़ने से वह भी घबरा रही है। 38 में से अधिकांश दलों के पास लोकसभा में कोई सीट नहीं है और न उनके जीतने की संभावना है फिर भी ऐसे अधिक से

अधिक दलों को भाजपा अपने साथ रखना चाहती है तो इससे उसकी समझदारी का पता चलता है। सूक्ष्म चुनावी प्रबंधन पर बल देने के कारण ही भाजपा ऐसा कर रही है। एक और चीज जो साफ हो गयी है कि मोदी सरकार के खिलाफ मजबूत विपक्षी गठबन्धन खड़ा हो चुका है। कुछ महीनों पहले तक यह कयास लगाना मुश्किल था कि 26 दल एक साथ आ जाएंगे और एक चुनाव पूर्व गठबन्धन बना पाएंगे। एक तो मोदी-कोप से कई छोटे दलों के नेताओं में भयमिश्रित असमंजस था तो दूसरा यह कि इन दलों में से कई राज्यों में एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं। केरल इसमें सबसे रोचक है जहाँ मुख्य मुकाबला इंडिया के घटक दलों- कांग्रेस और सीपीएम- के बीच ही है। यहाँ का मामला इतना रोचक है कि यहां भाजपा विरोध का कोई अर्थ ही नहीं है। यहाँ कांग्रेस को सीपीएम का विरोध करना है और सीपीएम को कांग्रेस का। एक बार को बंगाल में भी सीपीएम, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के साथ आकर भाजपा के खिलाफ लड़ने की संभावना बन सकती है लेकिन केरल में नहीं। इंडिया गठबन्धन को केरल-कोण से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि इंडिया को केवल भाजपा से ही संघर्ष नहीं करना है बल्कि आंतरिक संघर्ष भी बहुत ज्यादा करना है। आंतरिक संघर्ष को न्यूनतम रखना ही इंडिया की सफलता की पूर्व शर्त है। इस आंतरिक संघर्ष को न्यूनतम करने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं। एक तो गठबन्धन को चुनिंदा राज्यों में चुनाव बाद फलित किया जाय। बाकी जिन राज्यों में मुख्य मुकाबला बीजेपी से है उन राज्यों में चुनाव पूर्व गठबन्धन किया जाय। चुनाव पूर्व और चुनाव पश्चात के लफड़े में पड़ने से अधिक इसके लिए एक सीट पर एक उम्मीदवार की युक्ति कारगर होगी। यदि ऐसा हो पाता है तो इंडिया बंगाल, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, केरल की लगभग सभी सीटें तथा बिहार और महाराष्ट्र में अभूतपूर्व प्रदर्शन कर सकता है। यही नहीं 26 दलों के नेता जब उन राज्यों में भी प्रचार के लिए दौड़ेंगे तब जनता उनकी बातें सुन सकती है जहाँ भाजपा को सबसे अधिक उम्मीदें हैं। गठबन्धनों के चुनावी संघर्ष का स्वरूप चाहे जो भी हो लेकिन आगामी आमचुनाव में मुख्य रणबांकुरे कांग्रेस और भाजपा को ही रहना है। धन, प्रचार और कार्यकर्ता सभी दृष्टि से भाजपा मजबूत तो है ही। इसके अलावा इसमें भी कोई संदेह नहीं कि चुनाव बाद बुरी-से-बुरी हालत में भी वह सबसे बड़ा दल बनकर उभरेगी। परन्तु यदि कांग्रेस उससे राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में ठीक से भिड़े और लोकसभा की 70% से अधिक सीटें जीत ले, तो मोदी के लिए जरूर मुश्किल पैदा हो जाएगी। यह कांग्रेस के लिए बड़ा लक्ष्य हो सकता है लेकिन असम्भव नहीं। इन राज्यों में उसका संगठन भी सुदृढ़ है और नेतृत्व भी लोकप्रिय है। 10 सालों की केंद्रीय सत्ता विरोधी लहर यदि ज़रा भी चल गई तो कांग्रेस अचंभा कर सकती है। इसी अचंभे पर इंडिया में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका व हैसियत भी तय होगी और केंद्र में सरकार गठन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। यानी 2024 का निर्णय मूलतः कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। यह कैसे हो सकता है? इसका आकलन सरल है। यदि कांग्रेस भाजपा से 100 के आसपास सीटें छीनकर अपनी संख्या 150 के आसपास कर पाती है और भाजपा 200 पर थम जाती है तो राजनीतिक हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि चुनाव के बाद कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सहायक दल मिलेंगे। इंडिया में शामिल दलों के अलावा अन्य दलों का भी उसे समर्थन मिल सकता है। कुछ सरकार में शामिल हो सकते हैं और कुछ बाहर से समर्थन दे सकते हैं। एनडीए बनाम इंडिया की बाइनरी तो अब स्पष्ट हो चुकी है। एनडीए का भीतरी-बाहरी समीकरण भी स्पष्ट है। उसके नेता मोदी होंगे। घटक दलों को भाजपा के नेतृत्व में ही सब कुछ हासिल करना है। भाजपा सागर है तो वे उसकी बूंदें हैं। परन्तु, इंडिया में सब कुछ तय नहीं है। कौन नेता होगा? इस पर खुली घोषणा नहीं हुई है। शुरू में नीतीश कुमार पर चर्चा केंद्रित थी। पर जब से लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की बारात में शामिल होने की इच्छा जताई है, तब से यह कयास लगाया जा रहा है कि राजद को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है। इसके अलावा सीपीएम, डीएमके, एनसीपी, माले, एसपी को भी कोई खास समस्या नहीं होगी। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार हो सकता है चुनाव तक नेता घोषित किये जाने के पक्ष में न हों और बाद में अपने पक्ष में समीकरण बन जाने की कल्पना करते हों, पर नवम्बर-दिसंबर तक भारत जोड़ो यात्रा के संभावित दूसरे चरण के पूरा होते-होते यदि इंडिया मजबूत होता दिखता है तो उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। परन्तु राहुल गांधी की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले जानते हैं कि राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाने की नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री बनने से परहेज नहीं है, हो सकता है उनके सहयोगी दलों को भी न हो, पर 200 से कम सीटें लाने वाली कांग्रेस के प्रधानमंत्री वे नहीं होना चाहेंगे।

बापू की दिनचर्या

उपवास (भाग-2)

गतांक से आगे...

डॉ. एस. सी. दास का यह कथन उल्लेख्य है कि बापू उपवास करने में बहुत निपुण थे। उन्हें उपवास-विज्ञान का गंभीर ज्ञान था। ईश्वरीय विधान में उनका पूर्ण विश्वास था। अतः वे जानते थे कि मानवजाति की सेवा के लिए उनकी और जरूरत समझी गई तो ईश्वर उन्हें जरूर जीवित रखेगा। इसलिए उन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं होती और उपवास भर वे एक दार्शनिक की भाँति शांति का उपयोग करते इस प्रकार शारीरिक शक्ति कायम रखने के लिए देहगत भोजन के रासायनिक परिवर्तन में जो शक्ति खर्च होती है, उसे भी वे कम-से-कम खर्च करते। बापू के उपवास परीक्षाओं में से अक्षत निकल आने का कारण विविध शक्तियों का विकास, उनके आत्मनियंत्रण की विशेष शक्ति, उपवास संबंधी गूढ़ ज्ञान और उनके लापसिक जीवन में ढूंढा जा सकता है। बापू उपवास को ब्रह्मचर्य पालन का अनिवार्य अंग मानते। ये कहा करते कि इंद्रिय-दमन के हेतु से इच्छापूर्वक किए गए उपवास से उसमें बहुत सहायता प्राप्त होती है। अधिकतर उपवास करनेवालों की विफलता के संबंध में उनका कहना था कि यह मान लेना बिलकुल गलत है कि उपवास मात्र से सारा कार्य बन जाएगा। ऐसे उपवास को वे बाहरी उपवास बताते, क्योंकि उस अवधि में मन छप्पन भाँति के भोगों में लिप्त रहता है, इन विचारों का स्वाद लिया जाता है कि उपवास पूर्ण होने पर अमुक वस्तुएं खाएँगे। बाद में ऐसे लोग स्वादेंद्रिय तथा जननेंद्रिय दोनों पर संयम न हो सकने की बात करते हैं। उपवास से लाभ वस्तुतः तभी होता है, जब मन भी देह-दमन में सहयोग देता है। दूसरे शब्दों में-मन में विषय-वासना का श भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका मूल मन है। उपवास जैसे साधनों से प्राप्त होनेवाली सफलता बहुत होते हुए भी अपेक्षाकृत कम होती है। यह कहा जा सकता है कि उपवास करनेवाला भी विषयलिप्त रहता है, लेकिन उपवास के बगैर विषय-वासना का समूल विनाश हो नहीं सकता। इसीलिए बापू इसे ब्रह्मचर्य पालन का अनिवार्य अंग मानते। सामाजिक कुरीतियों तथा अनेक शारीरिक व्याधियों के निर्मूलन, अपने निकट के लोगों में सद्भावना या विवेक जागृत करने तथा आत्मशुद्धि के लिए भी बापू प्रायः उपवास करते।

क्रमशः ...

रक्षा मंत्री के बयान से पाकिस्तान में मची खलबली भारत का गुस्सा देख पाक ने दी शांति रखने की सलाह

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य में जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एलओसी पार करने की चेतावनी दी तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। एक ओर पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं तो दूसरी ओर भारत के रक्षा मंत्री ने ऐसी चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के बीच खलबली मच गयी है। पाकिस्तान में इस मुद्दे को लेकर सेना और सरकार के वरिष्ठ लोगों के बीच बैठकों का दौर जारी है। पाकिस्तान में यह सवाल उठ रहा है कि जिस तरह बार-बार भारत पीओके की बात कर रहा है तो कहीं उसने कोई बड़ी योजना तो नहीं बना रखी है? राजनाथ सिंह के ताजा बयान ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है जिसके चलते पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से आनन फानन में जारी किये गये बयान में भारत के रक्षा मंत्री की उस टिप्पणी की निंदा की गयी है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अपना सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार करने के लिए तैयार

है। पाकिस्तान ने कहा कि ''युद्ध भड़काने वाली बयानबाजी'' क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा है। इस्लामाबाद में विदेश कार्यालय ने कहा है कि पाकिस्तान किसी भी आक्रामकता के खिलाफ अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है।

पाकिस्तान विदेश कार्यालय के एक बयान में कहा गया, ''हम भारत को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह देते हैं क्योंकि उसकी आक्रामक बयानबाजी क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है और दक्षिण एशिया में रणनीतिक माहौल को अस्थिर करने वाली है।'' बयान में कहा गया है कि यह पहली बार नहीं है कि भारत के नेताओं और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान के बारे में ''अत्यधिक गैर-जिम्मेदाराना'' टिप्पणी की है।

हम आपको याद दिला दें कि कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। पांच अगस्त, 2019 को भारत द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो गए थे।

बहरहाल, जहां तक राजनाथ सिंह के बयान की बात है तो हम आपको बता दें कि लद्दाख के द्रास में बुधवार को 24वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर करगिल युद्ध स्मारक में अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा था कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, हम देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं... अगर इसके लिए एलओसी पार करना हो, तो हम वह भी करने के लिए तैयार हैं... अगर हमें उकसाया गया और जरूरत पड़ी तो हम एलओसी को पार कर जाएंगे।'' उन्होंने कहा था, ''करगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। जिस वक्त भारत, पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिये मुद्दों की सुलझाने की कोशिश कर रहा था... पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया।'' उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को ''राष्ट्र के दुश्मनों'' का खात्मा करने के लिए खुली छूट दी गई है।

देश की हर उपलब्धि की आलोचना करना चाहता है विपक्ष : एस. जयशंकर

■ राष्ट्रीय हित में राजनीति को रखें किनारे

नईदिल्ली। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि मैं पिछले महीने में हुए विकास के बारे में सदन को सूचित करना चाहता था। आपने पीएम की अमेरिका की बहुत सफल यात्रा देखी...मुझे बुरा लगा कि विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे देश की हर उपलब्धि की आलोचना करना चाहते थे। विदेश नीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम आम तौर पर एक साथ काम करते हैं। हम देश के भीतर बहस कर सकते हैं लेकिन देश के बाहर हमें एकजुट होकर प्रदर्शन करना चाहिए। आज विपक्ष का आचरण ऐसा होना चाहिए इस पर गौर किया जाना चाहिए, जब राष्ट्रीय हित की बात हो तो राजनीति को किनारे रख देना चाहिए और इसकी सराहना करनी चाहिए।

मणिपुर की स्थिति से संबंधित विपक्षी सदस्यों की मांगों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में गुरुवार को व्यवधान का सामना करना पड़ा और दोनों सदनों को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जहां लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए शुरू होने के तुरंत बाद स्थगित कर दी गई, वहीं राज्यसभा को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में कार्यवाही की शुरुआत से

ही शोर-शराबा देखने को मिला। विपक्षी दल के सदस्यों ने नियम 287 के तहत चर्चा सहित मणिपुर की स्थिति से संबंधित अपनी मांगों को लेकर नारे लगाए।

कई विपक्षी सदस्य काले कपड़े पहने हुए थे। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश नीति में नवीनतम विकास पर एक बयान दे रहे थे तो विपक्षी सदस्यों के नारे लगाने के कारण लगातार व्यवधान का सामना करना पड़ा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी कुछ देर के लिए मोदी, मोदी के नारे लगाकर उनका प्रतिवाद किया। अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह दशक भारत का है और देश का उत्थान अजेय है। धनखड़ ने उपसभापति के रूप में अपनी विदेश यात्राओं का जिक्र किया और कहा कि भारत का नागरिक होना बड़े सम्मान की बात है।

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि तय! पीएम को भेजा गया औपचारिक निमंत्रण

लखनऊ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में राम जन्मभूमि स्थल पर बन रहे भव्य मंदिर के पवित्र गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए औपचारिक रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। जनवरी 2024 में होने वाले इस समारोह में लगभग 10,000 मेहमान मौजूद रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि उन्होंने 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच कई तारीखों की पेशकश की है। हालांकि, उन्होंने कहा, सटीक तारीख प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित की जाएगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास द्वारा हस्ताक्षरित निमंत्रण पत्र में कहा गया है कि पीएम की उपस्थिति से भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने समारोह के लिए एक अचूक, अतिथि-उन्मुख सुरक्षा तंत्र तैयार किया है। अयोध्या प्रशासन सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है क्योंकि उसे श्रद्धालुओं के काफी संख्या में आने की उम्मीद है। मंदिर का भूतल इस साल दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, निर्माण कार्य अब 18 घंटे की शिफ्ट की जगह, चौबीसों घंटे चलाया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट ने कार्यबल को 550 से बढ़ाकर लगभग 1,600 मजदूरों और तकनीशियनों तक कर दिया है। गौरतलब है कि मार्च में राम मंदिर को महज 15 दिनों में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा का

दान मिला था।

अयोध्या राम मंदिर में %प्राण प्रतिष्ठा% समारोह 15-24 जनवरी, 2024 तक आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दिन अभिषेक समारोह में शामिल होंगे। हालांकि, तारीख अभी भी प्रधानमंत्री को ही तय करना है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर के कपाट प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के लिए खुलेंगे। आम श्रद्धालु 25 जनवरी 2024 से मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। भव्य उद्घाटन की तैयारी अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। सूत्रों ने कहा कि दुनिया भर में भारतीय दूतावास विभिन्न आयोजनों की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गर्भगृह का मुख्य द्वार सोने से मढ़वाया जाएगा, उस पर भी सोने की नक्काशी होगी। मंदिर का 161 फीट ऊंचा शिखर भी सोने से मढ़ा जाएगा।

अमेरिका ने चेताया, फिर भी चीन बाज नहीं आया

रूस को कर रहा घातक हथियारों की सप्लाई

वाशिंगटन। चीन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को ड्रोन और अन्य हथियारों की आपूर्ति की है। पोलिटिको ने बताया कि चीनी निर्माता सुरक्षात्मक गियर के साथ-साथ यूएवी जैसे महत्वपूर्ण मात्रा में उपकरण वितरित कर रहे थे जो तोपखाने की आग को निर्देशित कर सकते हैं और यूक्रेनी बलों पर ग्रेनेड गिराने में सक्षम हैं। चीनी कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई तस्वीरों में क्रू कट और चपटी नाक वाला एक लंबा, कोकेशियान व्यक्ति उसके कारखाने में बॉडी कवच का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। चीन एक तरफ तो शांति के लिए आह्वान करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर 17 महीने पुराने छेड़े गए युद्ध पर भौतिक प्रभाव डालने के लिए रूस को पर्याप्त गैर-घातक, लेकिन सैन्य रूप से उपयोगी उपकरण दे रहा है।

ऐसे ड्रोन हैं जिनका उपयोग तोपखाने की आग को निर्देशित करने या हथगोले गिराने के लिए किया जा सकता है और रात में दुश्मन को निशाना बनाने के लिए थर्मल ऑप्टिकल जगहें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये शिपमेंट पुतिन की युद्ध मशीन को बाधित करने के पश्चिम के प्रयासों में चीन के आकार की खामियों की ओर इशारा करते हैं। तथाकथित दोहरे उपयोग वाली तकनीक की बिक्री, जिसका नागरिक और सैन्य दोनों उपयोग हो सकता है, पश्चिमी अधिकारियों के लिए बीजिंग जैसी विशाल आर्थिक शक्ति का सामना न करने के कारणों की

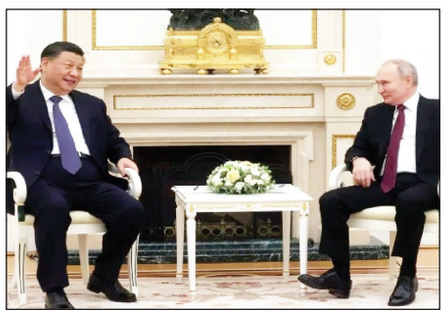

तलाश करने के लिए पर्याप्त अस्वीकार्यता छोड़ती है।

जून के महीने में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दावा किया था कि बीजिंग में कहा कि चीन ने यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस को हथियार नहीं भेजने का वादा फिर से किया है। ब्लिंकेन ने दो दिनों की बातचीत के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमें और अन्य देशों को चीन से आश्वासन मिला है कि वह यूक्रेन में इस्तेमाल के लिए रूस को घातक सहायता नहीं देगा। बता दें कि एंटनी ब्लिंकन ही थे जिन्होंने इससे पहले चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ऐसा होता है तो चीन को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इससे पहले पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर ने भी कहा था किरूस को हथियार भेजने से रोकने के लिए चीन के साथ संवाद किया गया है। हमने रूस को घातक समर्थन प्रदान करने के नकारात्मक परिणामों के बारे में चीन के साथ संवाद किया है।

बांग्लादेश के मंत्री का बड़ा बयान

भारत पर दबाव नहीं बना सकतीं विदेशी ताकतें

कोलकाता। बांग्लादेश के सूचना मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा बनाकर विदेशी ताकतें, उनके देश पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं। बांग्लादेश के मंत्री ने कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। बांग्लादेशी मंत्री ने कहा कि इन विदेशी ताकतों में भारत पर दबाव बनाने की ताकत नहीं है। महमूद ने कहा कि बांग्लादेश में अगले साल जनवरी में होने वाले आम चुनाव संविधान के तय नियमों के अनुसार ही होंगे।

कोलकाता प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए हसन महमूद ने कहा कि हमारे देश पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप सही नहीं हैं। बांग्लादेश में मानवाधिकार के हालात, उन देशों से बेहतर हैं, जो हम पर आरोप लगा रहे हैं। हसन महमूद ने कहा कि विदेशी ताकतें जो बांग्लादेश में मानवाधिकारों को लेकर

सवाल उठा रही हैं, वह हमारे देश पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रही हैं। अमेरिका में भी नस्लीय हमले होते हैं। हसन महमूद ने कहा कि अगर भारत में कोई मुद्दा बनता है तो इन विदेशी ताकतों में क्या सवाल उठाने की हिम्मत है? इसका जवाब है नहीं क्योंकि यह एक संप्रभु राष्ट्र का आंतरिक मामला है, लेकिन ये विदेशी ताकतें बांग्लादेश पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं क्योंकि बांग्लादेश भू-राजनीतिक स्तर पर बेहद अहम है।बांग्लादेश की चीन से नजदीकी के सवाल पर हसन महमूद ने कहा कि हाल के सालों में बांग्लादेश में चीन के निवेश में कमी आई है। महमूद ने माना कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को मिले हैं क्योंकि उनकी नीलामी की दर बेहद कम है।

हम जानते हैं सरकार नहीं गिरेगी, पर हमारे पास कोई चारा नहीं : अधीर रंजन

■ कांग्रेस सांसद ने कहा कि हमें मजबूरन अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है

नई दिल्ली। लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बुधवार को नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने को लेकर सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हम जानते हैं कि इससे सरकार नहीं गिरेगी, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। संसद में चल रहे मानसून सत्र में विपक्ष ने मणिपुर में जारी हिंसा को मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की है।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमारी मांग थी कि प्रधानमंत्री खुद आकर बोलें। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं। हमें मजबूरन अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। ये हमारी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इससे सरकार नहीं गिरेगी, पर हमारे पास कोई चारा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री देश के सामने

आकर मणिपुर पर कोई वार्ता करें।

कांग्रेस ने बुधवार को कहा कि लोकसभा में उसके सांसद गौरव गोगोई द्वारा पेश किया गया अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) का सामूहिक प्रस्ताव है तथा इस पर प्राथमिकता के आधार पर गुरुवार को ही सदन में चर्चा आरंभ होनी चाहिए। पार्टी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि मणिपुर के हालात ने मजबूर किया है कि यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। मनीष तिवारी ने कहा, यह कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि I.N.D.I.A के घटक दलों द्वारा सामूहिक तौर पर लाया गया है। पिछले 83-84 दिनों से मणिपुर में जो स्थिति बनी हुई है उस पर क़ानून-व्यवस्था चरमरा गई है, समुदाय के बीच विभाजन हो गया है। वहां सरकार नाम की चीज़ नहीं रह गई है। इन तथ्यों ने हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर किया है। कांग्रेस नेता ने कहा, ''नियम के अनुसार जब अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए मंजूर कर लिया जाता है तो उसके 10 दिनों के भीतर सदन में चर्चा होती है। लेकिन लोकसभा की परंपरा रही है कि जब भी यह प्रस्ताव आता है तो बाकी सारे कार्यों को रोककर इस पर चर्चा होती है।' गौरतलब बात है कि विगत नौ वर्षों में यह दूसरा अवसर होगा जब यह सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। इससे पहले, जुलाई, 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट दिया था। इस बार भी संख्याबल स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में है और निचले सदन में विपक्षी दलों के 150 से कम सदस्य हैं।

भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी के वादे पर कांग्रेस का तंज

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'देश के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की गारंटी वाले' बयान पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरना तय है और यह सच है, भले ही 2024 के चुनावों के बाद सरकार कोई भी बनाए। गौरतलब है, पिछले साल सितंबर में भारत यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। इस क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी शीर्ष चार स्थानों पर हैं। जयराम रमेश ने कहा कि अंकगणितीय अनिवार्यता पर व्यक्तिगत गारंटी देना मोदी जी की खासियत है। इस दशक में भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की भविष्यवाणी पिछले काफी समय से की जा रही है और इसकी गारंटी है- चाहे कोई भी अगली सरकार बनाए। इस बीच, रमेश ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर 26 दलों वाला विपक्षी गुट इंडिया सत्ता में आता है तो प्रधानमंत्री की भाजपा के तहत देश जिस रास्ते पर चलेगा, उसकी तुलना में विकास में एक %महत्वपूर्ण अंतर% होगा। विपक्षी गठबंधन की खूबी बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि मुख्य अंतर विकास के प्रकार का है, जिसकी इंडिया गारंटी देती हैं। ऐसा विकास जो सामाजिक रूप से कहीं ज्यादा समावेशी है, विकास जो नौकरी पैदा करता है खत्म नहीं, विकास जो हर जगह आय बढ़ाता है और विकास जो पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ है। कांग्रेस और 25 विपक्षी दल भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का मुकाबला करने और उसे केंद्र में लगातार तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए इंडिया (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन) बनाने के लिए एक साथ आए हैं।

राजस्थान चुनाव से जुड़े मुद्दे को लेकर सर्वे

■ अशोक गहलोत पहली पसंद कौन

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ही महीने शेष हैं। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जीत की तैयारियां लगातार जारी हैं। प्रदेश में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। एबीपी न्यू सी वोटर ने राजस्थान चुनाव से जुड़े मुद्दे को लेकर सर्वे किया है, जिसमें प्रदेश के मुद्दे से लेकर सीएम की पहली पसंद जैसे सवाल पर लोगों से राय मांगी। सीएम अशोक गहलोत 35 प्रतिशत के साथ लोगों के लिए सबसे पसंदीदा सीएम चेहरे के रूप में उभरे हैं। वहीं उनके बाद वसुंधरा राजे पर 25त्न प्रतिशत लोगों ने अपनी सहमति दी है। कांग्रेस के ही अन्य नेता और कई मौकों पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सचिन पायलट को राज्य की 19त्न जनता सीएम के रूप में देखना चाहती है। गजेंद्र सिंह शेखावत को 9 फीसदी, राज्यवर्धन राठौर का नाम 5 फीसदी और अन्य के समर्थन में 7 फीसदी लोग रहे।

महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा

बढ़ती कीमतें-28%
बेरोजगारी- 27%
भ्रष्टाचार-10%
बुनियादी सुविधाएं- 5%
अन्य मुद्दे- 30%

वसुंधरा राजे के काम से संतुष्ट हैं?

संतुष्ट- 26%
कुछ हद तक संतुष्ट-27%
संतुष्ट नहीं- 39%
कह नहीं सकते- 8%

अशोक गहलोत सरकार से संतुष्ट हैं?

संतुष्ट-39%
कुछ हद तक संतुष्ट-36%
संतुष्ट नहीं- 24%
कह नहीं सकते- 1%

बसपा का प्लान बी, मायावती और ओवैसी लड़ेंगे मिलकर लोकसभा चुनाव!

आशीष तिवारी

दिल्ली की सत्ता का एक बड़ा रास्ता उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि अब यूपी के सियासी गलियारों में तमाम तरह की रणनीति बनाई जाने लगी हैं। तमाम राजनीतिक दलों के बीच में बसपा ने भी राजनीतिक बिसात पर अपनी सियासी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं। कहने को तो मायावती ने सिरे से किसी भी राजनीतिक दल से सियासी गठबंधन को इनकार कर दिया है। लेकिन पार्टी से जुड़े सूत्रों का मानना है कि मायावती की झोली में लोकसभा चुनावों को लेकर दो तरह के महत्वपूर्ण प्लान तैयार हैं। पहले प्लान में लोकसभा चुनावों से पहले वह यूपी में एक विशेष जाति वर्ग में अपनी पकड़ बनाने को तैयार बैठे सियासी दल के साथ गठबंधन कर सकती हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहले पायदान पर खड़ी नजर आ रही है। जबकि दूसरा प्लान उनका पूरी तरह खुला है कि विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद वह गठबंधन के पत्ते खोलेंगी, जिसमें सरकार को समर्थन देने तक की बात कही जा रही है।

तो क्या ओवैसी के साथ होगा बसपा का गठबंधन

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन को लेकर इंकार कर दिया। सियासी गलियारों में चर्चा इसी बात की हो रही है कि मायावती ने गठबंधन में जाकर चुनाव लड़ने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन उनका यह इनकार सिर्फ विधानसभा के चुनावों तक है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे ही विधानसभा के चुनाव समाप्त होंगे, मायावती अपने सियासी पत्ते एक बार फिर से खोलना शुरू कर देंगी। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की हो रही है कि लोकसभा चुनावों से पहले मायावती और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर गठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि इस गठबंधन को लेकर बहुजन समाज पार्टी से जुड़े किसी भी नेता ने

खुलकर तो कुछ नहीं कहा लेकिन चर्चा इस बात की जरूर है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में बड़े स्तर पर सेंधमारी करके गठबंधन को मजबूत बना सकती हैं।

हालांकि किसी भी तरह की बातचीत से पहले बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी की ओर से चुनावी सीटों को लेकर के कई तरह के पेंच फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों की मानें तो बहुजन समाज पार्टी ओवैसी को चार से पांच सीटें देने पर राजी हो सकती है। इसको लेकर पार्टी के भीतर कुछ अंदरूनी चर्चाएं भी हुई हैं। लेकिन फिलहाल कहा यही जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी अगर गठबंधन में जाती है, तो वह इससे ज्यादा सीटों की दावेदारी करेगी। क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी को बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मजबूत पैठ बन सकती है। जबकि बहुजन समाज पार्टी मुस्लिमों के बिखरे हुए वोट पर कुछ हद तक अपने साथ और मजबूती से जोड़ भी सकेगी।

हालांकि उत्तर प्रदेश में मायावती और ओवैसी के बीच होने वाले गठबंधन के सवाल को ही सियासी जानकार सही फैसला नहीं मानते हैं। राजनीतिक विश्लेषक विष्णु एम कुमार कहते हैं कि मायावती और ओवैसी के बीच होने वाले गठबंधन की बात फिलहाल उनको समझ नहीं आ रही है कि ऐसा कोई गठबंधन हो भी सकता है। वह कहते हैं कि मायावती असदुद्दीन ओवैसी के साथ समझौता क्यों करेंगी वह भी तब जब वह खुद मुसलमान वोटों पर सीधे तौर पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहती हैं। विष्णु कहते हैं कि यह तो जानबूझकर अपने उस जनाधार को खत्म करने जैसा ही होगा जिसे आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और फिर ऐसा गठबंधन करके मायावती ओवैसी को अपनी मजबूत पकड़ वाले वोट बैंक को क्यों दे देंगी, जिसमे उनको लंबे समय तक कोई भला नहीं होने वाला। उनका मानना है कि ओवैसी अगर मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें मायावती को फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होगा। क्योंकि गठबंधन में मायावती का दलित वोट ओवैसी के हिस्से में जा सकता है और मुसलमान वोट जो मायावती को पहले से मिल रहा है वो ओवैसी के साथ आने या न आने से कम ज्यादा नहीं होने वाला। ऐसे में इस गठबंधन कि फिलहाल संभावना तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन वह कहते हैं कि सियासत में किसी भी परिस्थितियों में कुछ भी हो सकता है।

शिशु के पेट में गैस बनने पर आजमाएं ये उपाय, तुरंत मिलेगी राहत

नवजात शिशु को खास देखभाल की जरूरत होती है। माता-पिता को उन्हें दूध पिलाने से लेकर नहलाने और मालिश करने तक का खास ख्याल रखना पड़ता है। जरा सी भी गलती उनके लिए समस्या पैदा कर सकती है। नवजात शिशु बड़े बच्चों की तरह माता-पिता को अपनी समस्या बोलकर नहीं बता पाते हैं। ऐसे में मां ही उनके हाव-भाव देखकर उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करती है। ऐसी ही एक समस्या जो नवजात शिशु को अक्सर परेशान करती है वो है पेट में गैस बनना। अगर आपका बच्चा भी इस समस्या से परेशान रहता है तो अपनाएं ये घरेलू उपाय।

शिशु को गैस से राहत दिलाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे-

हींग-

गैस की शिकायत होने पर शिशु की नाभि पर हींग का पेस्ट बनाकर लगाएं। ऐसा करने से शिशु की गैस बाहर निकल जाएगी और उसे दर्द से निजात मिलेगी।

मालिश-

नवजात शिशु को गैस के दर्द से राहत दिलाने के लिए उसके पेट की मालिश करना न भूलें। इसके लिए शिशु को सबसे पहले पीठ के बल लिटाकर पेट पर थोड़ी देर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। शिशु की मालिश करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसके पेट पर ड्ड, रु और ड्ड अक्षर लिखने की नकल करें। इस %आई लव यू% मसाज तकनीक को अपनाने से शिशु की गैस बाहर निकल जाएगी।

दूध पिलाते समय बच्चे का सिर ऊपर रखें-

नवजात शिशु को बोतल से दूध पिलाते समय उसका सिर पेट से थोड़ा ऊपर की तरफ रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार बच्चा बोतल से दूध पीते समय तेजी से दूध खींचता है, जिसकी वजह से उसके पेट में हवा चली जाती है। लेकिन दूध पिलाते समय शिशु के सिर ऊंचा रखने से वह आसानी से डकार के साथ गैस को बाहर निकाल पाएगा।

पेट की सिंकाई-

पेट में गैस बनने से शिशु अगर परेशान हो रहा है तो उसे तुरंत राहत पहुंचाने के लिए उसके पेट की सिंकाई करें। इसके लिए गुनगुने पानी में तौलिया भिगोकर निचोड़ लें। इस तौलिए को शिशु के पेट के ऊपर रखें। इस उपाय को करने से शिशु को पेट में गैस और ऐंठन की समस्या में आराम मिलेगा।

घुटनों से साइकिल चलवाएं-

शिशु जब गैस पास नहीं कर पाता है तो दर्द से रोने लगता है। ऐसे में उसे राहत देने के लिए पीठ के बल लिटाकर उसके घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को उठाएं और साइकिल चलाने जैसा बिहेव करें। ऐसा करने से पेट में फंसी गैस बाहर निकल जाती है।

अधूरा पोषण करता है बच्चों की ग्रोथ को प्रभावित

बीमारियों में मिलेगी राहत

अधूरा पोषण करता है बच्चों की ग्रोथ को प्रभावित, यहां जानिए बच्चों के लिए जरूरी फूड्स के बारे में

इस समय पूरे परिवार के भोजन में ही पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। जिसका असर बच्चों की ग्रोथ पर भी पड़ रहा है। जंक फूड खाने वाले पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए जरूरी पोषण और फूड्स के बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी है।

बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में उनके भोजन और माता-पिता का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्यादातर पेरेंट्स इस समय वर्किंग हैं और वे दिन भर बिजी रहते हैं। उनके खुद के भोजन में जंक और प्रोसेस्ड फूड्स की मात्रा बढ़ती जा रही है। ऐसे में बच्चों को सही पोषण मिल पाना और भी मुश्किल हो गया है। जिससे बच्चे न केवल कमजोर और छोटे कद के हो रहे हैं, बल्कि उनके बाल, बोन्स और दांत भी कमजोर हो रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे की बेहतर ग्रोथ होते देखना चाहते हैं, तो इन फूड्स को उनके आहार में जरूर शामिल करें।

सही आहार और बच्चों की ग्रोथ

बच्चों के सही आहार में उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की सही मात्रा मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यूनिसेफ के अनुसार, बच्चों को 6 महीने की उम्र में उनका पहला भोजन शुरू करना चाहिए, जो पोषण से भरपूर होना चाहिए। छोटे बच्चों को दिन भर में बार-बार और पर्याप्त मात्रा में भोजन देना जरूरी है, क्योंकि उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

बच्चों के शारीरिक विकास के लिए उन्हें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की सही मात्रा मिलनी चाहिए। ये पोषक तत्व उनके ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने, हड्डियों, दांतों, और अंगों के विकास में मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, अनाज, दूध, डेयरी उत्पाद, मांस, और मछली जैसे खाद्य पदार्थ बच्चों को उचित पोषण प्रदान करते हैं।

इन चीजों से बनाएं दूरी

बच्चों के आहार में अधिक मीठा, नमक, चीनी और वसा वाले डिब्बाबंद स्नैक्स शामिल करने से उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। ये खाद्य पदार्थ उनके दांतों, शरीर के वजन नियंत्रण को ख़राब कर सकते हैं और उन्हें उच्च रक्तचाप, मोटापा, और सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, बच्चों को स्वस्थ और पौष्टिक आहार देने के लिए ये खाद्य पदार्थ अच्छे नहीं होते हैं।

बच्चों को बढ़ने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ देने चाहिए ये जानने के लिए हमने बात कि न्यूट्रिनिस्ट और वेट लॉस एक्सपर्ट शिखा कुमारी से।

1 वृद्धि और विकास में समस्या

सही और पर्याप्त पोषक तत्वों के अभाव में बच्चों के विकास में समस्या हो सकती है। खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो बहुत कम या अनपूर्ण आहार लेते हैं या उन्हें विभिन्न पोषण संबंधी समस्याएं होती हैं। इससे उनका विकास अवरुद्ध हो सकता है और वे अपनी उम्र के अनुसार नहीं विकसित हो सकते हैं।

2 बोन हेल्थ हो सकती है प्रभावित

विटामिन, खनिज और प्रोटीन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन से कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है, जबकि आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिससे थकान, कमजोरी हो सकता है।

3 कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली

खराब पोषण से बच्चों के शरीर का रोग-प्रतिरोधक प्रणाली धीरे-धीरे कमजोर होती है और उन्हें संक्रमणों का सामना करने में कठिनाई होती है। विशेष रूप से विटामिन और खनिजों की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, जो बच्चों को विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से प्रभावित कर सकता है।

4 ब्रेन हेल्थ पर भी पड़ता है असर

पोषण की कमी, विशेष रूप से आयरन, आयोडीन, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे प्रमुख पोषक तत्वों की कमी, संज्ञानात्मक कार्य और मस्तिष्क के विकास को ख़राब कर सकती है। इससे सीखने में कठिनाई, खराब एकाग्रता और व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

एल्युमीनियम के बर्तन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

रोटी पकाने का सही तरीका

दाल हो या सब्जी, अगर आप हर चीज के साथ रोटी खाना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए हैं। जी हां, रोटी खाने के शौकीन लोगों को शायद ही पता हो कि अगर वो रोटी पकाने के सही तरीका नहीं जानते हैं तो अनजाने में ही सही लेकिन वो कैंसर जैसे रोग को न्यौता दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप रोटी पकाकर उसे सही तरह से स्टोर करके नहीं रखते तो भी सेहत को नुकसान हो सकता है।

सालभर पहले हुए अध्ययन में भी यह दावा किया गया था एल्युमीनियम फॉइल भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे कैंसर हो सकता है। अध्ययन में दावा किया गया था कि कई लोग एल्युमीनियम फॉइल में रोटी लपेटकर टिफिन में ले जाते हैं, कई घरों में महिलाएं कैसरोल में रोटी इसमें लपेट रखती हैं। इससे हड्डियों से लेकर इम्युनिटी तक पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसको लेकर चिंता जताई थी।

15 से 20 मिनट पहले आटा गूंथ ले

अध्ययन में बताया गया है कि कुछ लोग रोटी को तवे पर कम पकाते हैं और तेज आंच पर उसे सेकते हैं। इसकी वजह से रोटी अंदर से कच्ची रह जाती है। ऐसी रोटी का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक है। रोटी को सही तरीके से पकाने के लिए 15 से 20 मिनट पहले आटा गूंथ ले। इसके बाद हल्की आंच पर तवे में रोटी को अच्छी तरह से सेक लें और फिर इसे सीधे आग पर पकाएं। इससे रोटी अंदर से पक जाएगी। जो सेहत के लिए अच्छी है।

सिगरेट-शराब की लत से जल्द मिलेगा छुटकारा

लौंग के अंदर मौजूद यूजेनॉल तत्व हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन इसका लाभ लेने के लिए लौंग का सही तरीके से सेवन किया जाना चाहिए। लौंग के नियमित सेवन से सिगरेट-शराब आदि की लत से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है।

लौंग को एक फायदेमंद जड़ी-बूटी होती है। लौंग के सेवन से व्यक्ति को अनगिनत फायदे होते हैं। लेकिन इसके फायदे के लिए लौंग का सही तरीके से सेवन किया जाना जरूरी होता है। आपको बता दें कि प्रतिदिन 2 लौंग नियमित रूप से चूसने से व्यक्ति की शराब और सिगरेट पीने की आदत पर कंट्रोल किया जा सकता है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको लौंग चूसने के फायदे और इसके सही तरीके से सेवन किए जाने के बारे में बताने जा रहे हैं।

इन लतों से मिलता छुटकारा

- मीठा खाने की लत
- मुंह की बदबू
- शराब की लत?
- दांत का दर्द
- अपच की समस्या
- फंगल इंफेक्शन
- जी मिचलाना और उल्टी
- सिगरेट व धूम्रपान की लत

सेवन का सही तरीका

एक्सपर्ट्स की मानें तों लौंग को मुंह में रखकर इसको धीरे-धीरे चूसना चाहिए। जितने लंबे समय तक आप इसके रस को चूसने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही लाभकारी होगी। बता दें कि लौंग को फौरन चबाने या निगलने का गलता नहा करना चाहिए। लौंग के अंदर पाए जाने वाले तेल में इसके औषधीय गुण छिपे होते हैं। इसलिए इसका धीरे-धीरे चूसकर सेवन किया जाना लाभकारी होता है।

लत ऐसे छोड़ें

अधिकतर सभी लोगों के लिए यह घरेलू उपाय असरदार साबित होता है। हालांकि कुछ लोगों पर इस घरेलू उपाय का असर न के बराबर दिख सकता है। यदि आपको इस उपाय से फायदा नहीं होता है तो आप शराब व सिगरेट की लत को छोड़ने के लिए किसी डॉक्टर की मदद बी ले सकते हैं।

लौंग के फायदे

लौंग के रस में यूजेनॉल तत्व पाया जाता है। लौंग में एनलजेसिक, एंटी-इंफ्लामेटरी, एनेस्थेटिक और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। लौंग के यह गुष कई समस्याओं में राहत प्रदान करते हैं।

[भविष्यफल]

मेष

आज आपका मन नए-नए कामों में लगेगा। दोस्तों के साथ मिलकर आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिजूलखर्ची पर कंट्रोल रखें अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। यात्रा योग बन रहे हैं। खरीददारी कर सकते हैं। बच्चों के साथ भावनात्मक सम्बन्ध बनेंगे।

वृष

आज आपकी आज आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। बिजनेस करने वाले लोगों को मिलाजुला फल मिलेगा। आपके सामने कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है जिसका सामना करने के लिए आप तैयार रहें। अनजाने लोगों के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत कीजिए।

मिथुन

आज आपका आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। आपको अपनी किस्मत का भरपूर सहयोग मिलने वाला है। पुराने रुके हुए काम पूरे होंगे। आपको अपनी मेहनत का मन मुताबिक फायदा मिल सकता है। जो लोग काफी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे.

कर्क

आज आपका आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। आप जिस क्षेत्र में कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलने के योग हैं। आपकी किसी बड़ी योजना का अच्छा फायदा मिल सकता है। भविष्य के लिए धन इकट्ठा करने में आप सफल रहेंगे।

सिंह

आज आपका आज का दिन फायदेमंद साबित होगा। रुके हुए कामों में गति आएगी। धार्मिक यात्रा योग। आप अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। अचानक अपनों से कोई खुशखबरी मिल सकती है। पैसा कमाने के कई मार्ग हासिल होंगे। आज आप पैसों का उधार लेन-देन मत कीजिए।

कन्या

आज आपका आज का दिन बेहद खुशनुमा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। किसी पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अचानक किसी महत्वपूर्ण मामले में फैसला लेना पड़ेगा। आपके द्वारा लिया गया फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है। प्यार के मामले में आप भाग्यशाली होंगे।

तुला

आज आपका आज का दिन बेहतरीन रहेगा सामाजिक क्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बेरोजगार लोगों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। जीवन में आज ढेरों खुशियां आएंगी। जीवनसाथी आपकी भावनाओं को समझेगा। प्रेम जीवन में सुधार आने की संभावना

वृश्चिक

आज आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग नजर आ रहे हैं। कार्यालय में आपके कार्यों की सराहना होगी। अचानक लाभ मिलने के योग हैं। आप अपनी मधुर वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। भाग्य प्रबल रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांस का अवसर मिल सकता है।

धनु

आज का दिन मौज मस्ती भरा व्यतीत होने वाला है। सामाजिक मेलजोल से आपको खुशी और सुकून मिलेगा। कामकाज में अच्छे नतीजे हासिल होंगे। नौकरी के क्षेत्र का माहौल आपके पक्ष में रहने वाला है। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, वह अपने प्रिय के साथ रोमांस भरा पल व्यतीत करेंगे।

मकर

आज आप जरूरतमंद लोगों की मदद करने का मौका मिल सकता है। व्यापार के सिलसिले में लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आमदनी में हुई बढ़ोतरी इसको संतुलित कर देगी। आपको अपना नजरिया सकारात्मक रखना होगा।

कुंभ

आज सकारात्मक बने रहना होगा। आपके मन में कोई पुरानी बात चिंता का कारण बन सकती है। आप कहीं पैसा निवेश कर सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको अपने किसी जरूरी काम में सफलता हासिल होगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा।

मीन

आज का दिन अति उत्तम रहेगा। लाभ के कई अवसर हाथ लग सकते हैं। आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा। खर्चों में कमी आएगी। बच्चों की तरफ से टेंशन कम होगी। पारिवारिक जीवन की परेशानियों का समाधान हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खानपान में रुचि बढ़ेगी।

इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा गोल्डन मिल्क

आजकल के दौर में अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते मोटापा बढ़ जाता है। बेली के आसपास जमा फैट काफी जिद्दी होता है। मोटापा बढ़ने के कारण कई गंभीर बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में इन चीजों को शामिल कर सकते हैं।

आजकल के दौर में मोटापा एक गंभीर समस्या बन गया है। मोटापे से न केवल हमारा फिगर खराब हो जाता है। बल्कि बढ़े हुए मोटापे के कारण कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर मोटापे के कारण पेट के आसपास के हिस्से में चर्बी जम जाती है। जो देखने में काफी ज्यादा खराब लगता है। बेली फैट को सबसे जिद्दी फैट माना जाता है। बेली फैट में कमर और पेट के आसपास फैट जमा हो जाता है। वहीं इससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। गलत खानपान और अनियमित लाइफस्टाइल के कारण मोटापा बढ़ने लगता है।

कुछ लोग मोटापे को कम करने के लिए कड़ी डाइट फॉलो करते हैं। लेकिन इसके बाद भी पेट और कमर के आस-पास जमा फैट कम नहीं होता है। जिसके कारण कई बार इंसुलिन सेंसिटिविटी हो सकती है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में मौजूद इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। इंसुलिन पैंक्रियाज ग?लैंड में बनता है। यह हमारे ब्लड से शुगर को सेल?स में ले जाने में सहायता करता है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होता है। साथ ही इसका हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है।

एक्सपर्ट्स ने जानिए बेली फैट कर करने के खास टिप्स

इंसुलिन सेंसिटिविटी

डाइटीशियन मनप्रीत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जानकारी देते हुए बताया कि जब भी हम खाना खाते हैं। तो हमारी बॉडी में पैंक्रियाज ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन नाम का हार्मोन छोड़ता है। हमारी कोशिकाओं के दरवाजों को खोलने के लिए इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। यह ग्लूकोज को कोशिकाओं में भेजने का काम करने के साथ ही उसे ऊर्जा के रूप में काम करवाता है। जब इस प्रक्रिया से ग्लूकोज हमारी सेल्स में पहुंच जाता है। तब खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल फिर से नॉर्मल होता है।

वहीं जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो हमारी कोशिकाएं इंसुलिन की ओर से सही प्रतिक्रिया नहीं देती है। जिसके कारण हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। पैंक्रियाज ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने के लिए कुछ और इंसुलिन भेजती है। लेकिन जो शुगर ब्लड में ऑब्जर्व नहीं हो पाती है तो बेली के आसपास चर्बी जमा होना शुरू हो जाता है। इसी कारण बेली फैट बढ जाता है।

इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएं

इंसुलिन सेंसिटिविटी को अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कर आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में किन-किन चीजों को बढ़ाना चाहिए।

गोल्डन मिल्क

हल्दी- एक चुटकी
मिर्च- एक चुटकी
घी- आधा टी स्पून
लौंग- एक
अदरक- आधा टी स्पून
दूध- 150 मि.ली

ऐसे बनाएं

सब चीजों को दूध में डालने के बाद इसे 5 मिनट के लिए उबाल लें। फिर इस दूध को सोने से पहले पीना चाहिए।

एलोवेरा-आंवला शॉट्स

आंवला जूस- 30 मि.ली
एलोवेरा जूस- 30 मि.ली
पानी- 60 मि.ली
ऐसे बनाएं

सब चीजों को एक साथ मिलाएं और पिएं। इसके बाद एक पानी का गिलास पी सकते हैं। ध्यान रखें कि इस पानी को सुबह के समय पीना चाहिए।

ये भी हैं लाभकारी

इंसुलिन सेंसटिविटी बढाने के लिए आप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं।

सीलोन दालचीनी- लंच के कुछ देर बाद दालचीनी(दालचीनी के फायदे) की चाय पिएं।

अदरक वाली चाय- शाम के समय अदरक वाली चाय पिएं।

मेथी दाने का पानी- सुबह खाली पेट मेथी दाने का पानी पिएं।

संक्षिप्त समाचार

मंत्री मरकाम ने किया एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण

धमतरी। प्रदेश के आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्री मोहन मरकाम ने आज धमतरी जिले के प्रवास के दौरान एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह का औचक निरीक्षण किया। वे सुबह 8 बजे छात्रावासों की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर छात्रावास परिसर, कमरों, किचन व शौचालय की साफ-सफाई का निरीक्षण कर संतोष प्रगट किया। साथ ही बच्चों के द्वारा प्रार्थना और योगाभ्यास करते देख खुशी व्यक्त किए। श्री मरकाम ने बच्चों से छात्रावास की दिनचर्या के बारे में रू-ब-रू चर्चा की और भोजन सहित वहां मिलने वाली अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे तथा सही जवाब देने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर संस्था की प्राचार्य श्रीमती अर्चना नेताम, शिक्षक श्री लीलाराम नेताम, अधीक्षक श्री दौलतराम ध्रुव, श्रीमती गणेशिया ध्रुव सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

चुनाव से पहले आईपीएस अफसर ने किया मतदान, फिर ली सेल्फी

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है। ऐसे में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जगदलपुर में जागरूकता शिविर लगाया गया है। इसमें ईवीएम और वीवीपैट मशीन को लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। जिला कार्यालय में लगाए गए इस कैंप में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने प्रतीकात्मक वोट दिया और इसके बाद सेल्फी जोन में सेल्फी भी ली। इस अवसर पर कलेक्टर विजय दयाराम के.भी मौजूद रहे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के मार्गदर्शन में विधानसभा निर्वाचन 2023 में शत-प्रतिशत मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित कराने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट मशीन व मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट व सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केंद्र बनाए गए हैं।

बीए, बीकाम, बीएससी की पूरक परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक

रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की पूरक परीक्षाओं के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बीए, बीकाम, बीएससी, बीसीए, बीपीई जैसे पाठ्यक्रमों में पूरक की पात्रता रखने वाले छात्र-छात्राएं 31 जुलाई तक सामान्य शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। वहीं एक से छह अगस्त तक अभ्यर्थी 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ आवेदन सर सकते हैं। बीए, बीकाम के लिए पूरक परीक्षा की शुल्क 820 रूपये, बीएससी, बीसीए के लिए 1,075 और बीपीई के लिए 1,120 रूपये निर्धारित की गई है। पूरक परीक्षाएं अगस्त में होगी, विश्वविद्यालय प्रबंधन पूरक परीक्षाओं के लिए जल्द समय सारणी जारी करेगा। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा एक मार्च से शुरू होकर मई तक चली थी।वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे पिछले दिनों जारी किए गए थे। इस बार बीए, बीकाम, बीएससी, बीसीए सहित अन्य कक्षाओं का परीक्षा परिणाम बहुत कमजोर आया है।खासकर ग्रेजुएशन प्रथम वर्ष में बड़ी संख्या में छात्रों को पूरक की पात्रता मिली है। इसलिए इस बार पूरक परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या अधिक होने की संभावना है।

विभागीय परीक्षा 1 से 8 अगस्त तक आयुक्त रायपुर ने जारी किए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के गृह-सी विभाग द्वारा विभागीय परीक्षा 01 अगस्त से 08 अगस्त 2023 तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा राजधानी रायपुर के शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बैरन बाजार में होगी। परीक्षा के लिए महाविद्यालय के कक्ष क्रमांक 56 को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। रायपुर संभाग आयुक्त डॉ संजय अलंग ने परीक्षा संबंधी सभी तैयारियां समय पर पूरे करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है, साथ ही संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में विभिन्न विभागों के परीक्षा में शामिल होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को भी सूचित करने के निर्देश संभाग आयुक्त ने जारी किए है।

संविदा कर्मियों पर एस्मा का असर नहीं सरकार कर सकती है नियमित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी कर्मचारियों की जानकारी मांगी है। शासन के इस आदेश के बाद विभागवार जानकारी संकलन का काम भी शुरू हो गया है। इधर शासन द्वारा एस्मा लगाये जाने के बाद भी हड़ताली संविदा कर्मी विरोध प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। सेवा समाप्ति का भी उनमें डर नजर नहीं आ रहा है. हालांकि सरकार की ओर से बार बार प्रस्ताव दिया जा रहा है पहले हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे। नियमितीकरण भी इतना आसान नहीं हैं कितना वित्तीय भार कोष पर पड़ेगा यह भी बड़ा सवाल है। विभाग के कामकाज पर भी असर दिखने लगा है क्योकि कई जगहों पर संविदा कर्मियों के भरोसे ही काम चल रहा है। कुल मिलाकर पेंच फंस गया है। यदि बड़े फैसले पर मुहर लगती है तो एक बड़ा चुनावी फायदा में चुनाव में मिलेगा।

भूपेश सरकार ने 34 वादे पूरे किए, जारी किया वायदों का ब्योरा

रायपुर। पिछले विधानसभा चुनाव में वादों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने वायदों का ब्यौरा पेश कर बीजेपी को घेरा है। पूर्व इस दौरान कांग्रेसी नेता पूर्व सीएम रमन सिंह पर जमकर बरसे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 सालों तक झूठ फरेब की सरकार चलाने वाले और वायदा खिलाफी करने वाले डॉ. रमन सिंह एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं। उनका बयान कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा नहीं किया, सिर्फ 19 वायदे पूरे किए हैं। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में कुल 36 वायदे किये थे, जिसमें से हमने 34 वायदे पूरे किए हैं।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हम रमन सिंह को अपने घोषणा पत्र की प्रति जिसमें हमारे वायदों का पूरा हिसाब है और भाजपा के संकल्प पत्र जो उन्होंने 2003 और 2008 तथा 2013 में जनता से वायदा किया था, दोनों को भेज रहे हैं, जिसको वो पढ़ लें तो शायद उन्हें अपने आप को आईने में देखने में शर्म आयेगी। जिस प्रदेश ने उनको 15 सालों तक सिर आंखों पर बैठाया उसके साथ उन्होंने धोखा किया था। हमने जनघोषणा पत्र के 34 वायदे पूरा किया। शराबबंदी, लोकपाल के दो वायदे अधूरे हैं, जिसमें हमने शराबबंदी के लिये ठोस प्रयास शुरू किया है। 100 से अधिक दुकानों को बंद किया। आज हमारे प्रयासों से रमन सरकार के समय जो छत्तीसगढ़ शराब की खपत में प्रति व्यक्ति गोवा के बाद पहले नंबर पर था वह अब 18वें नंबर पर है। जनघोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का काम हमारी सरकार बनने के पहले घंटे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू किया था, किसानों की कर्जा माफ करने से वह अनवरत पांच सालों तक चलते रहा। यही कारण है कि कांग्रेस की सरकार के प्रति जनता का भरोसा रोज बढ़ते जा रहा है, 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव सभी में जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रति भरपूर आर्शीवाद दिया है।

भाजपा का वायदा खिलाफी का इतिहास

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि साल 2003 में हर आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देने का वायदा किया, 15 सालों तक नहीं दिया। 2003 में ही हर आदिवासी परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया, नौकरी देना दूर सरकारी नौकरी का सिस्टम बंद कर दिया, वायदा किया था हर बेरोजगार को 500 बेरोजगारी भत्ता देने का नहीं दिया। किसानों से चुनाव दर चुनाव धान पर बोनस देने का वायदा किया चुनाव के बाद कभी बोनस नहीं दिया। 2100 रू के धान खरीदी करने का वायदा किया था नहीं दिया। वायदा किया था किसानों का दाना-दाना धान खरीदेंगे 10 क्विंटल की लिमिट लगा दिया था,

कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के आंदोलन के बाद रमन सरकार ने 15 क्विंटल किया था, जिसे इस वर्ष से कांग्रेस सरकार ने बढ़ा कर 20 क्विंटल कर दिया है। रमन सिंह अपने वायदा खिलाफी से हमारी तुलना करने की कोशिश कर रहे दोनों के घोषणा पत्रों को उनको पढ़ना चाहिये। हकीकत समझ आ जायेगी।

- कांग्रेस ने किसानों के कर्जमाफी का वायदा पूरा किया। 2500 में धान खरीदी का वायदा पूरा किया।
- बेरोजगारी भत्ते का वायदा पूरा किया।
- कर्मचारियों से किया वायदा पूरा किया, 1 लाख भर्तियां करने का वायदा पूरा किया।
- आदिवासियों को जमीन वापस करने का वायदा पूरा किया।
- खाद्य सुरक्षा के वायदे के तहत 72 लाख राशन कार्ड बनाये।
- स्वास्थ्य के अधिकार के तहत 65 लाख परिवार खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के दायरे से दाई दीदी क्लिनिक हाट बाजार क्लीनिक शुरू किया।
- शिक्षा के अधिकार में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले। आरटीई को मजबूती से लागू किया।
- ग्रामीण और शहरी आवास में 239730 शहरी और 11 लाख 76 हजार 150 ग्रामीण आवास बनाये शेष आवासों के लिये 3200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया।
- वन अधिकार कानून के तहत 4 लाख 41 हजार व्यक्तिगत और 50 हजार वन अधिकार पट्टे दिया और पेसा कानून के नियम बनाये गये।
- शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 42 प्रतिशत किया, शिक्षा विभाग के 25000 कर्मचारियों का संविलियन किया।
- 33 हजार अनियमित कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी
- महिला स्व सहायता समूह का 19 करोड़ का कर्ज माफ किया
- गोठानों के माध्यम से महिला समूह को समृद्ध बनाया जा रहा, हमने जो कहा था हमारी सरकार ने वह पूरा किया है।

पत्रकारवार्ता में प्रभारी महामंत्री रवि घोष, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेंद्र वर्मा, अजय साहू, नितिन भंसाली, अजय गंगवानी, प्रकाश मणि वैष्णव, विकास बजाज, सत्यप्रकाश सिंह, राजेश चौबे उपस्थित थे।

कांग्रेस नेता सिंहदेव ने क्यों की अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग?

रायपुर। इस समय मणिपुर में हिंसा और वहां महिलाओं से हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। मणिपुर की परिस्थियों को लेकर पार्टियां एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रही है। इन सब के बीच एक अजीब बयान छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का आया है। वो कहते हैं कि देश का पीएम अमित शाह को बना देना चाहिए। ऐसा वो क्यों बोले ? इसके पीछे भी राजनीति है। हांलाकि इस पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का बयान सामने नहीं आया है।

दरअसल सिंहदेव रायपुर में मणिपुर के हालातों पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। पीएम मोदी के मणिपुर की घटना पर जिम्मेदारी नहीं लेने पर नाराजगी जताते हुए, वो बोले, कांग्रेस समेत विपक्ष इस मुद्दे पर गृह मंत्री के बजाय प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है। मणिपुर में कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। महिलाओं के साथ क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। अगर एफआईआर होने के 77 दिन बाद कार्रवाई शुरू की जाती है, तो जवाबदेह कौन है ? पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को इसके बारे में पता होगा। देश प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है और हर कोई मणिपुर की वास्तविक स्थिति जानना चाहता है। सिंहदेव की नाराजगी यहीं नहीं रूकी। उन्होंने कहा अगर प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर घटना की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दें। फिर अमित शाह देश को जवाब दे सकते हैं।

सिंह देव के इस बयान ने बीजेपी क्या? कांग्रेस के नेताओं को भी चौंका दिया है। अपनी बात आगे बढाते हुए सिंह देव ने कहा कि मणिपुर की घटना बेहद संवेदनशील है। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेताओं को पत्र लिखा है। मणिपुर घटना पर संसद में चर्चा के लिए सहयोग मांगा है। कांग्रेस इस मुद्दे पर सहयोग कर रही है। मणिपुर अत्यधिक संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में से एक है। जहां तनाव की स्थिति बनी हुई है।

पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा पर बयान दिया था। उन्होंने अपने बयान में छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लिया था। संसद में चर्चा के दौरान मंत्री पीयूष गोयल ने फिर छत्तीसगढ़ का नाम लिया। इसके बाद से ही छत्तीसगढ़ के नेता मोदी सरकार पर हमलावर हैं। सीएम भूपेश बघेल भी मणिपुर हिंसा पर केन्द्र सरकार को घेर चुके हैं।

निगम, मंडल, आयोग में अनुभवी कांग्रेसियों को स्थान मिलेः रिजवी

रायपुर। कांग्रेस में अपने 45 वर्षों के कांग्रेसी इतिहास का हवाला देते हुए मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने कहा है कि चर्चा है कि निगम, मंडल, आयोग एवं विभिन्न प्रदेश स्तरीय समितियों में नऐ चेहरों को लिया जाना तय ह। यह अच्छी पहल है। इस गठन में तरमीम करते हुए कहा है कि ऐसे गठन में सीनियर कांग्रेसियों की उपेक्षा न होने पाए इसका ध्यान रखना आवश्यक है। प्रदेश में लगभग 12 प्रतिशत सीनियर सिटीजन हैं उन्हें नकारा न जाए तथा जिन लोगों ने अपनी जवानी से लेकर अभी तक कांग्रेस में सेवारत है उनकी अनदेखी न करते हुए उपयुक्त निगम, मंडल एवं आयोग तथा समितियों के गठन के समय निष्ठावान कांग्रेसियों की पूर्व सेवाओं के मद्देनजर उन्हें भी समुचित स्थान देना चुनाव पूर्व गठित होने वाली समितियों में उचित होगा यह वक्त का तकाजा है।

रिजवी ने अपने व्यक्तिगत् सुझाव में कहा है कि विधानसभा चुनाव को मात्र चार माह ही शेष है। किसी को तीन-चार माह के लिए नियुक्ति देना तुष्टिकरण की श्रेणी में आ जाऐगा। तीन-चार माह में होने वाले चुनाव के पश्चात् किसी को पदस्थ होने वाले नेताओं की नियुक्ति चुनाव में योगदान एवं मेहनत को देखकर ही किया जाना मेरी नजरों में उचित होगा। यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि अविभाजित मध्यप्रदेश के सन् 1998 में चुनाव पूर्व सभी निगम, मंडल एवं विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने इस्तीफा ले लिया था ताकि नया मुख्यमंत्री जो भी आऐ उसे नियुक्तियों में कोई हिचक या कठिनाई उत्पन्न न हो।

आईटीआई व्यावसायिक प्रशिक्षण के छत्तीसगढ़ मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना

- भारत सरकार के प्रशिक्षण निदेशालय ने दिशा निर्देश तैयार करने के लिए गठित की समिति
- छत्तीसगढ़ से इस समिति में एक सदस्य नामांकित करने का किया अनुरोध

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हायर सेकेण्डरी के साथ छात्रों को आईटीआई प्रमाण पत्र प्रदान करने के लागू किए गए संयुक्त पाठ्यक्रम की तर्ज पर अब केंद्र सरकार पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटिग्रेटेड कार्यक्रम लागू करना चाहती है। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है, यह समिति स्कूल शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार करेगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय के निदेशक द्वारा इस समिति में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि नामांकित करने का अनुरोध किया गया है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के चयनित हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र जो साथ-साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए स्कूलों एवं आईटीआई के समन्वय के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं विद्यार्थियों की रुचि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है।

प्रदेश में इस पाठ्यक्रम के तहत आई.टी.आई. की परीक्षा में सफल प्रशिक्षणार्थियों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ के बारहवीं बोर्ड के प्रमाण पत्र के साथ-साथ राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा आई. टी. आई. का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2021 से 2023 के सत्र में स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त करने की योजना 116 विकास खंडों के 119 स्कूलों एवं आईटीआई में प्रारंभ की गई है। जिसमें विद्यार्थियों ने आईटीआई के 10 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इससे युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए विभिन्न कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। योजना के तहत उद्यमिता कौशल को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।

मानवीय जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है पेड़ पौधों का होना: सत्यनारायण

- डागा कालेज का यह परिसर हरियाली के लिए पहचाना जाएगा : अजय

रायपुर। श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय के एनएसएस के सदस्यों द्वारा आज वृक्षारोपण महोत्सव का आयोजन श्रीमती प्रमिला गोकुलदास कन्या महाविद्यालय के नए परिसर बोरिया खुर्द में किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित पूर्व मंत्री व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह वन संपदा केवल अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए नहीं अपितु हमारे मानवीय जीवन को बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सर्वाधिक वन संपदा होने के बावजूद भी तेजी से नगरीकरण हो रहा है। जलवायु को समायोजित करने का जिम्मा युवाओं के ऊपर सर्वाधिक है।

वही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अजय तिवारी, अध्यक्ष शासी निकाय ने छात्राओं से आव्हान किया कि सभी छात्राएं एक एक पौधे को गोद लेते हुए एवं प्रत्येक माह में दो बार यहां आकर उन पेड़ों का जतन करें। उन्होंने कहा भविष्य में यह परिसर हरा भरा परिसर के रूप में पहचाना जायेगा। पेड़ पौधों की अहमियत कितनी है हमने कोरोकाल के दौरान देख लिया जब आक्सीजन की आवश्यकता के लिए लोग ऐसे सुकून भरे जगहों की तलाश करते थे। आपके घर,संस्थान के आसपास पेड़ पौधे जरूर हों न हो तों स्वंय लगावें व दूसरों को प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दानदाता सदस्य डागा महाविद्यालय श्री गोकुल दास डागा, जयपुर के समाजसेवक केके शर्मा, बोरिया खुर्द के पूर्व सरपंच रामाधार साहू, महाविद्यालय परिषद के सदस्य आरके गुप्ता ,अध्यक्ष स्काउट गाइड सुरेश शुक्ला, सुधीर मुखर्जी वार्ड के पार्षद निर्मलकर, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ संगीता घई, एनएसएस प्रभारी कुमारी दुर्गा चंद्राकर एवं समस्त प्राध्यापक गण उपस्थित रहे।

औषधीय जड़ी-बूटियों को संरक्षित करने की दिशा में करें काम : साय

- सीएसआईडीसी के अध्यक्ष ने वनौषधि पार्क बनाने पर दिया जोर

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) के अध्यक्ष डॉ. नंद कुमार साय ने बुधवार को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज की समीक्षा की। बैठक में डॉ. साय ने कहा कि प्रदेश के स्थानीय वैद्यों की पहचान कर औषधीय जड़ी-बूटियों को संरक्षित करने के लिए कार्य योजना तैयार किया जाए। उन्होंने औद्योगिक विकास के तहत छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड से समन्वय कर वनौषधि पार्क बनाने पर भी जोर दिया। बैठक में मरवाही विधायक डॉ. के.के. ध्रुव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना पोर्ते, कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया, वन मंडलाधिकारी श्री सत्यदेव शर्मा, एसडीएम पेंड्रारोड श्री पुष्पेंद्र शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

सीएसआईडीसी के अध्यक्ष डॉ. साय ने कहा कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला वन और आदिवासी बाहुल्य जिला है, यहां वनौषधि जड़ी-बूटियों की कमी नहीं है। उन्होने औद्योगिक विकास के तहत वनौषधि पार्क भी प्रस्तावित करने कहा। डॉ साय ने औषधीय जड़ी-बूटियों के गुणों के बारे में अपने स्वयं के अनुभव भी साझा किए। उन्होने हड्डी जोड़, जहरीले सांप, बिच्छु का विष उतारने, पीलिया खत्म करने आदि के बारे में बताते हुए कहा कि जड़ी बूटियों के जानकार वैद्यों कि पहचान करें और वनौषधि पार्क बनाने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि अश्वगंधा, गिलोय आदि वनौषधियों का प्रभाव काफी कारगर है। वनौषधियों के उपयोग से किसी तरह का दुष्प्रभाव भी नहीं होता है।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने बताया कि जिले में लेमन ग्रास की खेती के साथ ही औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए मरवाही विकासखंड के ग्राम पथर्रा, सेखवा एवं मड़ई के 10 महिला स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया है। औषधीय पौधों की खेती के लिए केंवची क्षेत्र में भी कार्य योजना प्रस्तावित है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पहले जिले में 31 अक्टूबर 2000 तक 749 सूक्ष्म, लघु उद्योग पंजीकृत थे, जिसमें 94.82 लाख का निवेश एवं 1508 व्यक्ति रोजगार में नियोजित थे। राज्य गठन 1 नंवबर 2000 से 31 मार्च 2020 तक 380 पंजीकृत सूक्ष्म, लघु उद्योग जिसमें निवेश राशि 36 करोड़ 66 लाख 69 हजार और 1833 लोग उद्योगों में नियोजित है। 1 अप्रैल 2020 से 28 अप्रैल 2023 तक 21 उद्योग उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त हैं, जिसमें 18 करोड़ 39 लाख 20 हजार पूंजी निवेश एवं 196 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इन पंजीकृत उद्योगों में मुख्यतः हॉलर एण्ड फ्लोर मिल, राईस मिल, फेब्रीकेशन, ईंट निर्माण, बर्तन निर्माण, ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, फ्लाई एश ब्रिक्स, एल्युमिनियम प्रोडक्ट, आरसीसी पोल, हर्बल प्रोडक्ट, फिनाईल आदि इकाईयां संचालित है। इसके साथ ही नई औद्योगिक नीति 2019-2024 के तहत जिले में 301 प्रस्तावित नये इकाईयों ने उद्यम आकांक्षा प्राप्त किया है, जिसमें 85 करोड़ 94 लाख 62 हजार रूपए का पूंजी निवेश एवं 1234 लोगों के लिए रोजगार प्रस्तावित है।

आदिवासी गांवों में भाजपा मनाएगी दिवाली

रायपुर। केंद्र की मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा आदिवासी वोटरों को साधने में जुट गई है। प्रदेश भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव से पहले इन 12 जनजातियों के गांवों तक पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का आभार प्रकट करने का कार्यक्रम बनाया है। इसके तहत बूथ स्तर पर दिवाली से पहले ही भाजपा दीये जलाकर, मिठाई बांटकर और पटाखे फोड़कर केंद्र सरकार का आभार प्रकट करेगी।

रायगढ़, महासमुंद और सरगुजा में होगी बड़ी सभा

पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा तीन बड़े कार्यक्रम करने वाली है। इसमें रायगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी को आभार प्रकट किया जाएगा। महासमुंद के सरायपाली और सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा को बुलाने की तैयारी है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि दशकों से अपने अधिकारों से वंचित छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इस बात को मोर्चा गांव-गांव तक पहुंचाएगा। कार्यकर्ता लोगों को बताएंगे कि इस विषय को आगे बढ़ाते हुए भाजपा ने किस तरह से विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाने में भूमिका निभाई। साथ ही मोदी सरकार ने उसे कानून का जामा पहनाया।

छत्तीसगढ़ की आबादी पौने तीन करोड़ से ज्यादा है। इनमें 1.96 करोड़ से अधिक मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 34 प्रतिशत आदिवासी मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल 90 सीटों में एसटी के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 27 आदिवासी सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा में 11 सीटों में से 4 सीटें आरक्षित हैं। बस्तर, कांकेर, रायगढ़ और सरगुजा लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ बस्तर लोकसभा सीट में जीत दर्ज की थी जबकि तीन सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। विधानसभा की 29 आदिवासी सीटों के अलावा अन्य 17 सीटें हैं जहां 20 प्रतिशत आदिवासी निवासरत हैं। सबसे अधिक बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं जहां सभी सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। इन विधानसभा तक भाजपा इस संदेश को पहुंचाने के लिए काम करेगी।

इन्हें मिला है एसटी का दर्जा

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र व विशेष पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का पीढ़ियों से अधिकार व लाभ नहीं मिलना सबसे बड़ी विसंगति थी। अब प्रदेश की भारिया भूमिया के समानार्थी भूईया, भूईयां, भूयां, धनवार के समानार्थी धनुहार धनुवार, नगेसिया, नागासिया के समानार्थी किसान, सावर, सवरा के समानार्थी सौंरा, संवरा, धांगड़ के साथ प्रतिस्थापित करते हुए सुधार, बिंझिया, कोडाकू के साथ साथ कोड़ाकू, कोंध के साथ-साथ कोंद, भरिया, भारिया, पंडो, पण्डो, पन्डो को जनजाति वर्ग में शामिल किया गया है। इससे करीब 10 लाख जनजातियों को फायदा मिलेगा।

डा. रमन सिंह ने सरकार को लिखे तीन पत्र

वादों की दिलाई याद, भड़की कांग्रेस

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की कांग्रेस सरकार को तीन पत्र लिखे हैं। इनमें उन्होंने सरकार को वादा पूरा करने का जिक्र किया है। डा. सिंह ने दो पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एक पत्र शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे को लिखा है।

उनकी ओर से साझा किए गए पत्र में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण और दिवंगत शिक्षकों के अनुकंपा नियुक्ति की मांग की गई है और स्कूल शिक्षा मंत्री से विद्यामितान अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि 36 में से 19 मुद्दों पर क्रियान्वयन की कार्रवाई ही नहीं हुई। आखिरी तीन महीने का वक्त है, सरकार नियमितीकरण करें। वादे पूरे नहीं होने पर भाजपा की सरकार आएगी तो नियमित करेंगे।

कांग्रेस की कुनितियों ने किसान की जान ले ली: साव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छुइहा के एक किसान कन्हैया सिन्हा द्वारा आत्महत्या करने के कारण एक बार फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार का घोर किसान विरोधी चरित्र बेनक़ाब हो गया है। श्री साव ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में की गई घोषणाओं को पूरा नहीं करने के कारण प्रदेश के किसान हलाकान हो चले हैं और हताश होकर आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं। छुइहा के किसान की आत्महत्या का मामला इसकी तस्दीक करता है। श्री साव ने मृतक किसान के परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि मृतक किसान की जेब से मिले सुसाइड नोट से किसानों की कर्जमाफी के सरकारी दावों की पोल खुल गई है। आत्महत्या से पूर्व मृत किसान ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वादे के बावजूद उसका कर्ज माफ नहीं किया। मृत किसान का ऐक्सिस बैंक में ऋण खाता है। श्री साव ने कहा कि कन्हैया एक तो कर्ज न चुका पाने के कारण परेशान था, वहीं लो-वोल्टेज के चलते उसकी चार एकड़ की रबी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। भाजपा बिजली आपूर्ति की समस्या पर सतत प्रदेश सरकार को आगाह करती रही है। पिछले तीन-चार सालों से फसल नहीं होने, कर्जमाफी नहीं होने और साथ ही फसल बीमा नहीं होने के कारण कन्हैया चहुँओर परेशानी से घिरा हुआ था। अपने सुसाइड नोट में भी मृतक किसान ने दाने-दाने के लिए मोहताज होने और पाई-पाई के लिए परेशान होने की बात कही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि कन्हैया का कोई और विकल्प नहीं होने की बात कहकर आत्महत्या करना प्रदेश के लिए एक कलंकपूर्ण व दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रदेश की भूपेश सरकार जिस तरह किसानों के नाम पर लगातार झूठ बोलती आ रही है, उसके मुँह पर कन्हैया की आत्महत्या एक करारा तमाचा है। श्री साव ने कहा कि ऐसी किसान विरोधी झूठी सरकार को एक क्षण भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि प्रदेश सरकार मृतक किसान के शोक-संतप्त परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करे। श्री साव ने कटाक्ष किया कि अपने %खानदानी राजनीतिक आकाओं% की चाटुकारिता करने के लिए उत्तर प्रदेश में जाकर 50-50 लाख रुपए का मुआवजा बाँटने वाले मुख्यमंत्री बघेल को छत्तीसगढ़ के किसानों की जरा भी फिक्र नहीं है। जब भी छत्तीसगढ़ के किसानों को राहत राशि देने का मौका आता है, मुख्यमंत्री बघेल किसानों की जिंदगी की कीमत पाँच-दस हजार रुपए आँकते हैं।

कैट और मेटा भारत में 10 मिलियन व्यापारियों को डिजिटल बनाएंगे

रायपुर। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू, अमर गिदवानी, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि देश भर में छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने के प्रयास में, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और वैश्विक कंपनी मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप द्वारा अपनी पार्टनरशिप में एक बड़ा आयाम देते हुए देश में 10 मिलियन स्थानीय व्यापारियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित और कुशल बनाने का आज दोनों ने संयुक्त रूप से ऐलान किया। साझेदारी का लक्ष्य सभी 29 भारतीय राज्यों में 11 भारतीय भाषाओं में हाइपर-स्थानीय डिजिटल प्रशिक्षण के साथ व्यवसायों के लिए विकास के अवसरों को उजागर करने के लिए डिजिटलीकरण प्रयासों को अंतिम व्यापारी तक पहुँचाना है।

पूरे भारत में 40,000 व्यापारी संगठनों से जुड़े लगभग 8 करोड़ व्यापारियों के अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, कैट व्यवसायों को उनके स्टोरफ्रंट को डिजिटल बनाने और उनके 'डिजिटल' निर्माण में मदद करने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करने के लिए व्यापक डिजिटल और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई कार्यशालाओं की एक श्रृंखला देश भर में आयोजित करेगा जिसमें वहाट्सएप के बिजनेस ऐप पर 'दुकान', जिसमें उन्हें कैटलॉग, क्लिक रिप्लाई, क्लिक टू व्हाट्सएप जैसी सुविधाएँ जो ऐप पर उपलब्ध हैं, के बारे में शिक्षित करना शामिल है, जो छोटे व्यवसायों को अपने ग्राहकों के साथ कुशलतापूर्वक जुड़ना आसान बनाते हैं

इन वर्षों में, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ने पूरे भारत में सूक्ष्म, लघु व्यवसायों और एकल उद्यमियों को अपने व्यवसाय के लिए एक पेशेवर डिजिटल पहचान बनाने के साथ-साथ नए बाजारों की खोज करने और अपने ग्राहकों की सेवा करने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रवेश द्वार प्रदान किया है। यह साझेदारी भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाकर और नए युग की उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाकर संपन्न व्यापार समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम ळें

कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेन्द्र दोशी ने कहा, ''तेजी से विकसित हो रही व्यावसायिक जरूरतों के साथ, प्रौद्योगिकी, विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकती है। हमारा मानना है कि खुद को बेहतर बनाने के लिए सही उपकरणों के साथ, भारत भर के व्यापारी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के नए तरीके सीखकर लाभान्वित हो सकते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो पहुंच और सफलता प्रदान कर सकता है वह अद्वितीय है।

हम 'व्हाट्सएप से व्यापार' कार्यक्रम पर मेटा के साथ अपनी साझेदारी का विस्तार करने के लिए उत्साहित हैं, जिसे भारत के 29 राज्यों में 10 मिलियन व्यापारियों को कौशल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह साझेदारी व्यापारियों और व्यवसायों को अधिक व्यापक ग्राहक आधार बनाने, अपने व्यवसाय को बढ़ाने और भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में और भी योगदान देने में मदद करेगी।

हड़ताल पर जाएंगे 3 हजार से ज्यादा डॉक्टर

रायपुर। प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स और पोस्ट पीजी रेजिडेंट्स 1 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। स्टाइपेंड और बॉन्ड कम करने की मांग को लेकर ये हड़ताल होगी।रायपुर के अलावा सरगुजा, कांकेर, जगदलपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव के सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स भी काम बंद कर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने आज अस्पताल में काली पट्टी लगाकर मरीजों का इलाज किया।

छत्तीसगढ़ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉ प्रीतम दास ने बताया कि छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टर्स को मिलने वाला स्टाइपेंड दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहद कम है। उन्होंने बताया कि आस-पास के स्टेट एमपी, झारखंड से भी कम स्टाइपेंड प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स को मिलता है। दूसरे प्रदेशों में जहां 95 हजार रुपए तक दिया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ में 50-55 हजार रुपए ही मिलते हैं। किसी भी प्रदेश में 2 साल का बॉन्ड नहीं भरवाया जाता है। केवल छत्तीसगढ़ में ही ऐसा हो रहा है। बीते 4 साल में मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। इसके चलते मजबूरन अब हड़ताल का कदम उठाना पड़ा है।प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की संख्या 3 हजार से ज्यादा है। ये सभी प्रदेश अलग-अलग जिलों के मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। इसके साथ ये लोगों का इलाज भी करते हैं। प्रीतम दास ने बताया कि आज काली पट्टी लगाकर केवल सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है।

कांग्रेस छात्र संगठन की गुंडागर्दी और नवमतदाता सम्मेलन का ढोंग : जयंती पटेल

रायपुर। पं. रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के परिसर में स्थित पं.दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नवमतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति रही आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित थे लेकिन किसी वजह से आदत से मजबूर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओ का तेवर गर्म हो गया और वे गुंडागर्दी में उतारू हो गए मामला इतना बढ़ गया की उन्होंने कांच की साज सज्जा से बने दरवाजे तक को तोड़ दिया आनन फानन में कर्मचारियों ने उसे साफकरवाया ताकि अन्य किसी प्रकार की हानी से बचा जा सके साथ ही एनएसयूआई कार्यकर्ता पुलिस से अभद्रता भी करने लगे पुलिस ने एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया है। इस पर भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने कहा की जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का कांग्रेस शासन काल में जहां अपराध चरम पर वही कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्ता का दुरुपयोग करने में आमादा है कभी बीच चौराहे में पुलिस वालो को धमकाया जाता है की हमारे चाचा महापौर है और पुलिस विभाग कार्यवाही करने जगह 500? के चालान में मामला रफा दफा कर देती है ।

छत्तीसगढ़/राजधानी — प्रमुख समाचार

किसान प्रणाम योजना नया धोखा: दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा किसानों को गुमराह कर रही है। किसान प्रणाम योजना किसानों के साथ नया धोखा है। हकीकत यह है कि केंद्र की किसान विरोधी, उद्योगपति हितैषी मोदी सरकार किसानों के साथ लगातार छल कर रही है। न तो किसानों को वादे के मुताबिक लागत का दोगुना मूल्य मिल रहा। न ही केंद्र सरकार ने कृषि और किसान हित में कोई कदम उठाए। उर्वरको की सब्सिडी खत्म करने जैविक खाद के प्रमोशन का षडयंत्र किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि यहां किसानों की सरकार है। किसानों ने भाजपा को ठुकराकर कांग्रेस को चुना है। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से राजनीतिक प्रतिशोध निकाल रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ किसान सम्मान निधि में भेदभाव किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के किसानों को रासायनिक खाद के लिए तरसाया जा रहा है। केंद्र सरकार यहां के किसानों की जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध नहीं करा रही। मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों की समृद्धि में बाधक बनी हुई है। मोदी सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को राहत देने के नाम पर जो ताजा ढोंग किया है, उसका छत्तीसगढ़ के अन्नदाता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला।

कांग्रेस जो कहती है पूरा करती है भाजपा का काम धोखा देना: ठाकुर

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादाखलाफी का मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के निवास के पते पर कांग्रेस सरकार में 34 वादों के पूरा होने की सूची और साथ में भाजपा के 2003, 2008, 2013 के झूठ का पुलिंदा को लिफाफा में बंद करके भेज रहे है। ताकि भाजपा के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र और अपने घोषणा पत्र को ईमानदारी से पढ़ें और आत्म अवलोकन करें किस प्रकार जनता से किए वादे को पूरा किया जाता है।प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है, कांग्रेस ने 2018 के घोषणा पत्र में 36 बिंदुओं को समाहित किया था। सरकार बनने के बाद अब तक घोषणा पत्र के 34 वादों पर कांग्रेस की सरकार पूर्णता काम की है जिससे प्रदेश की जनता खुशहाल हुई है और बचे दो बिंदुओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस सरकार में चलाए जा रहे योजना के लाभार्थी पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, अरुण साव सहित भाजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता है लेकिन दलीय प्रतिबद्धता के चलते भाजपा के बड़े नेता जनता के बीच झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं।

कांग्रेस राज में महिलायें ज्यादा सुरक्षित: सुशील आनंद

रायपुर। सुकमा पोटा केबिन में मासूम बच्ची के साथ हुई घटना पर भाजपा स्तरहीन और असंवेदनशील राजनीति कर रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा इस घटना को मणिपुर की घटना से ध्यान भटकाने के लिये उपयोग करना चाह रही जो भाजपा के घृणित मानसिकता का परिचायक है। घटना जैसे ही सामने आई तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया, घटना के अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोषी छात्रावास अधीक्षिका पर भी पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कांग्रेस के राज में अपराधियों पर पर्दा नहीं डाला जाता है। अब अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही होती है। मासूम बच्ची के साथ हुई घटना पर स्तरहीन राजनीति करने वाली भाजपा को रमन सरकार के 15 सालों को देखना चाहिए जब प्रदेश में हर रोज तीन बलात्कार की घटना होती थी हर तीसरे दिन एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना होती थी। जब भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बेटा आदिवासी बेटी के साथ दुराचार कर फरार हो जाता है तो समूची भाजपा उसके बचाव में जुट जाती है। भानुप्रतापपुर में पॉक्सो एक्ट और मासूम बच्ची के साथ दुराचार के आरोपी को प्रत्याशी बना कर पूरी भाजपा उसके प्रचार में घूमती है।

पीएम प्रणाम योजना किसानों के जीवन में खुशहाली लाएगी: शर्मा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति किसानों को पीएम प्रणाम योजना लागू कर अनेक सौगातें देने के लिए प्रदेश भाजपा व प्रदेश के किसानों की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित की है। उल्लेखनीय है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के लिए 17 हजार करोड़ रुपए की राशि जारी की। गुरुवार को सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड खाद लॉन्च कर किसानों को समर्पित की गई और खाद के लिए आगामी वर्ष के लिए 3.8 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी पैकेज घोषित किया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और विकास की दृष्टि से लगातार काम कर रही है। किसान समृद्धि केंद्र पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और किसानों के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई देने पहुंचे श्री शर्मा ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने और खेती की तकनीक को उन्नत बनाने की दृष्टि से किए जा रहे कार्यों को केंद्र सरकार गति प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पूरे देश में किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की है जहां पर किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित होंगीं। इसी के साथ सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड के तौर पर यूरिया खाद के एक नए तीसरे प्रकार को लॉन्च किया गया। इस नई यूरिया गोल्ड खाद से किसानों को बहुत फायदा होगा।

भूपेश बतायें कि सिंहदेव झूठे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता: चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस जन घोषणा पत्र के वादों की पूर्ति पर कांग्रेस के विरोधाभासी दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जनता कांग्रेसी घोषणा पत्र के जनक और तीन महीने के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के उस कबूलनामे को सच माने, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 12 वादे पूरे किए हैं, अथवा कांग्रेस प्रवक्ता के दावे को सत्य माने, जिसमें कहा गया है कि 36 में से 34 वादे पूरे किए जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताना चाहिए कि उनके उप मुख्यमंत्री असत्य बोल रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता? सरकार झूठी है अथवा कांग्रेस? नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस में किसी भी मामले में कभी एक राय रही नहीं। अब यह अंतर्कलह इतनी बढ़ गई है कि झूठ बोलने में भी इनमें सामंजस्य नहीं है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस ने संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि उन्होंने जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वादे पूरे कर दिए हैं। अभी कुछ दिनों पहले विधानसभा सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ने बाकायदा एक मीडिया इंटरव्यू में कबूल किया कि हमने 12 वादे पूरे किए हैं। 12 वादों पर कार्य हो रहा है और 12 वादों को हमने नहीं छुआ है। इस हिसाब से अब सरकार की चलाचली की बेला में जो एक तिहाई वादे पूरे करने का जो दिखावा किया गया है।

किसान समृद्धि केंद्रों में बड़ी संख्या में जुटे छत्तीसगढ़ के किसान

■ पीएम मोदी ने देश के किसानों को दी सवा लाख समृद्धि केंद्र की सौगात

रायपुर। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की सहूलियत के लिए देशभर में सवा लाख से अधिक किसान समृद्धि केंद्र की शुरुआत की है। इन समृद्धि केंद्रों में किसानों के आवश्यकता के सभी सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही किसानों के हित में चलने वाली समस्त शासकीय योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध होगी इन केंद्रों में किसानों को परामर्श देने के लिए विशेषज्ञ भी उपलब्ध कराए जाएंगे। कुल मिलाकर यह किसानों के लिए एक दुकान, सभी प्रकार का समाधान का केंद्र होगा। श्री साहू ने बताया कि मोदी जी किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पित हैं। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ किसानी की लागत कम करने के लिए रासायनिक खाद में अभूतपूर्व छूट दे रहे हैं, वहीं अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी अभूतपूर्व वृद्धि कर रहे हैं। जहां भारत के किसानों को यूरिया ?266 प्रति बोरी में मिलती है वही उतनी ही यूरिया पाकिस्तान में ?800 में बांग्लादेश में ?720 में चीन में 2100 रुपए में और अमेरिका में ?3000 में किसानों को दी जाती है।

इसके अतिरिक्त भारत के मोटे अन्न को श्रीअन्न के नाम से पूरे विश्व में बाजार दिलाने के लिए मोदी जी ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है। इस प्रयास को आशातीत सफलता भी मिल रही है। इससे ना केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और विश्व के पटल पर हमारे भारत के किसानों की पहचान बनेगी। किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ किसान परिवारों के खाते में अबतक 260000 करोड रुपए से भी अधिक राशि डाली जा चुकी है। चूंकि किसान ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं अत: ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष ध्यान है इसके तहत गांव-गांव में सड़कें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान, घर-घर पानी पहुंचे इसलिए नल जल योजना, प्रत्येक घर में शौचालय, सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालय सहित कई विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। साथ ही पीएम ने खेतों की मिट्टी का परीक्षण कराने की महती योजना भी चलाई है। जिससे किसानों को यह पता चल सके की किस खेत में किस तत्व की कमी है और उसके अनुरूप वह अपनी खाद का उपयोग करें ताकि खेतों में अनाज का अधिकतम उत्पादन हो सके।

मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सेवानिवृत सैनिकों को सम्मानित किया गया

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा आज कृषि महाविद्यालय रायपुर के संगोष्ठी कक्ष में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत कारगिल युद्ध के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर वीरों का वंदन किया गया। इस कार्यक्रम में आठ सेवानिवृत सैनिको, सूबेदार और कोमोडर उपस्थित हुए जिनका अभिनंदन कर उन्हें सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रीय सेवा योजना, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. राजकुमार वर्मा, राज्य एन.एस.एस. अधिकारी एवं पदेन उप सचिव डॉ नीता वाजपेई, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय, डॉ. जी.के. दास की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में सामाजिक सेवा के साथ-साथ राष्ट्र प्रेम और समर्पण, सेवा भावना जागृत करना है। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा वृक्षा रोपण भी किया गया।कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉ. पी.के. सांगोडे, कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वागत भाषण दिया गया और पंच प्रण की शपथ भी उपस्थित जन समुदाय को दिलाई गई। इसके पश्चात सभी फौजियों द्वारा प्रेरणादायक उद्बोधन दिए गए। इस वृहद आयोजन में पं. रविवि के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. गजपाल तथा उनके 30 कार्यक्रम अधिकारी एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के समस्त कार्यक्रम अधिकारी तथा बड़ी संख्या मे स्वयंसेवक उपस्थित हुए।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.